

[2025] 11 एस.सी.आर. 60 : 2025 आईएनएससी 1192

जैनुल

बनाम

बिहार राज्य

(2014 की आपराधिक अपील सं. 1187)

07 अक्टूबर 2025

[जे. बी. पारदीवाला* और आर. महादेवन, न्यायमूर्ति गण]

विचार के लिए मुद्दा

उच्च न्यायालय ने यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार सत्र वाद सं. 124/1989 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की, जिसमें यहाँ अपीलकर्ताओं को दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ-साथ धारा 149 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था। क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।

हेडनोट्स †

दंड संहिता, 1860- धाराएं 302 और 149-अभियोजन पक्ष का मामला कि अभियोजन साक्षी-20 अपने भाई के साथ अपने खेत में गया था-आरोपी सं. 2, 16, 17 और 21 क्रमशः 400-500 व्यक्तियों के साथ हथियारों के साथ अभियोजन साक्षी-20 के खेत के पास छिपे हुए थे-उन्होंने अभियोजन साक्षी-20 और उसके भाई पर हमला किया।-अभियोजन साक्षी-20 के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई-शोर सुनकर, अभियोजन साक्षी-3, 4, 5, 6 और 10 क्रमशः एक एसएम के साथ अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुँचे-आरोपियों ने उन पर भी हमला किया और एसएम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियोजन साक्षी-20 के बयान को प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया। 24 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया-मुकदमे के समापन पर, 21 व्यक्ति दोषी ठहराए गए- 21 दोषियों में से 19 ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की-उच्च न्यायालय ने 12 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और 7 को बरी

*लेखक

कर दिया-इस प्रकार, जिन 12 दोषियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी, वे इस न्यायालय में अपील के लिए आए-हालाँकि, जहाँ तक दो अपीलकर्ताओं का संबंध था, अपीलें रद्द कर दी गईं- तदनुसार, वर्तमान दो अपीलें 10 दोषियों से संबंधित हैं:

अभिनिर्धारित: यह मामला पाँच घायल चश्मदीद गवाहों और घटना के दो प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्यों के इर्द-गिर्द घूमता है-साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही में तथ्यात्मक विसंगतियाँ और अलंकरण हैं जो मामले की जड़ पर प्रहार करती हैं। - घायल चश्मदीद गवाह, अभियोजन साक्षी-20, जिसके पुलिस बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, के मौखिक साक्ष्य से संकेत मिलता है कि उसका आरोपियों के साथ जमीन के समझौते को लेकर कोई विवाद नहीं था। अभियोजन साक्षी-20 का बयान उसके *फर्दबयान* से अलग है। अपनी मौखिक गवाही में, अभियोजन साक्षी-20 ने स्वीकार किया कि हमले के बाद वह बेहोश हो गया था और इसलिए, वह उन हमलावरों के नाम नहीं बता सका जिन्होंने क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 6 और 10 पर हमला किया था। इसके विपरीत, उसके *फर्दबयान* में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6 और 10 ने उसे सूचित किया था कि विभिन्न हथियारों से लैस चालीस अन्य लोगों ने हमले में भाग लिया था। - यह विरोधाभास उसकी विश्वसनीयता की जड़ पर प्रहार करता है - इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-3 ने यह भी कहा कि उसने अभियोजन साक्षी-20 को चालीस हमलावरों के नाम कभी नहीं बताए थे, जिससे गवाह की विश्वसनीयता और कम हो गई - अभियोजन साक्षी-3, एक घायल चश्मदीद गवाह, ने अपने मौखिक साक्ष्य में क्रमशः आरोपी सं. 12 और 10 पर प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया है - उसने कहा कि आरोपी सं. 10 ने उसके पैर पर गंडासे से हमला किया - हालाँकि, अभिलेख पर मौजूद चिकित्सा साक्ष्य न केवल गवाह के पैर पर किसी भी चोट की अनुपस्थिति को इंगित करता है, बल्कि यह भी कि गंडासे से लगी चोट आमतौर पर एक चीरा हुआ घाव बन जाती है - इसके अलावा, आँखों के बयान और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास है - अभियोजन साक्षी-5, एक घायल चश्मदीद गवाह, ने अपने मौखिक साक्ष्य में क्रमशः आरोपी सं. 8 और 6 पर प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया है - हालाँकि, चिकित्सा साक्ष्य गवाह द्वारा बताए गए हमले के बयान का समर्थन नहीं करता है - अभियोजन साक्षी-4 की मौखिक गवाही यह है कि वह किसी भी अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहता है - इसके विपरीत, वह कहता है कि घटनास्थल पर बड़ी सं. में लोग थे, और वह हमलावरों और दर्शकों के बीच अंतर नहीं कर पा रहा था 7, 13 और 14 को क्रमशः केवल अभियोजन साक्षी-6 द्वारा फंसाया

गया है - उनकी उपस्थिति या भागीदारी को किसी अन्य गवाह की गवाही से कोई समर्थन नहीं मिलता है - अभियोजन साक्षी-20 द्वारा सर्वव्यापी पहचान को छोड़कर आरोपी सं. 17 के खिलाफ भी कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है - यह न्यायालय यह मानता है कि आरोपीगण क्रमशः 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं - साथ ही, अभियोजन साक्षी-20 के बयान को प्राथमिकी नहीं माना जा सकता था, क्योंकि घटना की पहली सूचना अस्पताल में बयान दर्ज होने से पहले ही पुलिस तक पहुँच चुकी थी - यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है - एक मामला उस मानक को प्राप्त करता है जब उसके सभी कड़ी दृढ़ता से स्थापित होते हैं और एक उचित व्यक्ति की नज़र में पहचानने योग्य होते हैं - वर्तमान मामले में अभियोजन का संस्करण तथ्यों के सत्य प्रतिपादन पर आधारित प्रतीत नहीं होता—साक्षियों के मौखिक बयान न तो एक-दूसरे का समर्थन करते हैं और न ही चिकित्सीय अभिलेखों से मेल खाते हैं—महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं त्रुटियाँ मामले की जड़ तक जाती हैं, और ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन ने अपने प्रमाण का भार निर्वहन किया है—अतः, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश, उस सीमा तक जिसमें अपीलकर्ताओं को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, निरस्त किया जाता है। [कंडिका 65-68, 72, 73, 82, 83, 86, 91]

दंड संहिता, 1860- धारा 149-आवश्यक:

अभिनिर्धारित: i) पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा होना चाहिए; ii) उस गैरकानूनी जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए; iii) किया गया अपराध उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, या iv) जमावड़े के सदस्यों को यह ज्ञान होना चाहिए कि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष अपराध किए जाने की संभावना है। [कंडिका 45]

दंड संहिता, 1860 -धारा 149-प्रावधान का पहला और दूसरा भाग:

अभिनिर्धारित: भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में प्रावधान है कि यदि किसी गैरकानूनी जमावड़े (5 या अधिक व्यक्तियों का) के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य (जैसा कि धारा 141 में परिभाषित है) की पूर्ति हेतु कोई अपराध किया जाता है, या यदि जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त अपराध किए जाने की संभावना है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करते समय उस जमावड़े का सदस्य

था, उस अपराध का दोषी होगा - प्रावधान का पहला भाग गैरकानूनी जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपराध किए जाने की परिकल्पना करता है - जबकि, प्रावधान का दूसरा भाग गैरकानूनी जमावड़े के किसी सदस्य की ओर से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे अपराध किए जाने की संभावना के बारे में जानकारी को समाहित करता है। [कंडिका 46, 47]

दंड संहिता, 1860 -धारा 149-अभिव्यक्ति "सामान्य वस्तु के अभियोजन में":

अभिनिर्धारित: "सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि किया गया अपराध सीधे तौर पर सभा के सामान्य उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए, या साक्ष्य के मूल्यांकन पर, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि कार्य उस सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। [कंडिका 49]

दंड संहिता, 1860 -धारा 149-गैरकानूनी सभा-किसी भी सदस्य का रचनात्मक दायित्व:

अभिनिर्धारित: भारतीय दंड संहिता की धारा 149 किसी गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्यों को रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाती है, जब ऐसे जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से कोई अपराध किया जाता है या जमावड़े के सदस्यों को पता था कि ऐसा अपराध होने की संभावना है - हालांकि, ऐसा दायित्व केवल इस बात के प्रमाण पर ही लगाया जा सकता है कि कार्य एक सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया था - एक बार जब गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों के बीच एक सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व स्थापित हो जाता है, तो यह साबित करना अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक सदस्य ने एक स्पष्ट कार्य किया है - इस प्रावधान के तहत दायित्व तब आकर्षित होता है जब यह निश्चित हो जाता है कि किसी व्यक्ति को पता था कि किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में एक संभावित परिणाम था, जिससे वह गैरकानूनी जमावड़े का "सदस्य" बन जाता है। [कंडिका 50, 51]

दंड संहिता, 1860 – धारा 149 – जब सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो केवल निष्क्रिय दर्शक हों:

अभिनिर्धारित: इस तथ्य का पता लगाते समय, यह विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय दर्शक थे, जो सभा के सामान्य उद्देश्य की जानकारी के बिना, निष्क्रिय जिज्ञासा के कारण सभा में शामिल हुए थे, क्योंकि

ऐसे व्यक्तियों को गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता है - क्योंकि, धारा 149 का केंद्र "सामान्य उद्देश्य" है। [कंडिका 52]

दंड संहिता, 1860 - धारा 149 - निर्दोष दर्शक और गैरकानूनी सभा का सदस्य:

अभिनिर्धारित: घटनास्थल पर मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं बना देती, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि ऐसे आरोपी ने भी इसका सामान्य उद्देश्य साझा किया था - एक मात्र दर्शक, जिसकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दायरे में नहीं आएगा - अभियोजन पक्ष को, यथोचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिस्थितियों के माध्यम से, यह स्थापित करना होगा कि आरोपी व्यक्तियों ने गैरकानूनी सभा का एक सामान्य उद्देश्य साझा किया था - यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति एक निष्क्रिय दर्शक है या एक निर्दोष दर्शक है, परीक्षण वही है जो एक सामान्य उद्देश्य के अस्तित्व का पता लगाने के लिए लागू होता है - एक सामान्य उद्देश्य का अस्तित्व प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अनुमानित किया जाना है, जैसे: क) वह समय और स्थान जिस पर सभा का गठन किया गया था; (ख) अपराध स्थल पर या उसके आस-पास उसके सदस्यों का आचरण और व्यवहार; (ग) समूह का सामूहिक आचरण, जो व्यक्तिगत सदस्यों से भिन्न है; (घ) अपराध के पीछे का उद्देश्य; (ङ) घटना के घटित होने का तरीका; (च) ले जाए गए और इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति; (छ) पहुँचाई गई चोटों की प्रकृति, सीमा और सं., और अन्य प्रासंगिक विचार। [कंडिका 54]

दंड संहिता, 1860 - धारा 149 - ठोस और विश्वसनीय सामग्री - न्यायालय द्वारा सावधानीपूर्वक विचार:

अभिनिर्धारित: जहाँ बड़ी सं. में व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोप हों, वहाँ न्यायालय को अस्पष्ट या सामान्य साक्ष्य के आधार पर सभी को दोषी ठहराने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए - इसलिए, न्यायालयों को कुछ ठोस और विश्वसनीय सामग्री की तलाश करनी चाहिए जो आश्वासन दे - केवल उन लोगों को दोषी ठहराना सुरक्षित है जिनकी उपस्थिति न केवल प्राथमिकी के चरण से लगातार स्थापित होती है, बल्कि जिनके विरुद्ध ऐसे प्रत्यक्ष कार्य भी किए गए हैं जो गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को बढ़ावा देते हैं। [कंडिका 61]

साक्ष्य-घायल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही का मूल्यांकन:

कानून में एक घायल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि उस व्यक्ति

पर लगी चोटें इस तथ्य को विश्वसनीयता प्रदान करती हैं कि गवाह घटनास्थल पर मौजूद था- न्यायालयों एक घायल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को विश्वसनीयता प्रदान करती हैं, यह मानते हुए कि गवाह अपने वास्तविक हमलावर को बिना सजा के नहीं जाने देना चाहेगा - इस प्रकार, जब तक कि प्रमुख विरोधाभासों और विसंगतियों के कारण किसी प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य पर अविश्वास करने के ठोस आधार न हों, आमतौर पर ऐसे साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए। [कंडिका 63]

न्याय दृष्टान्त

मिजाजी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1959] पूरक 1 एससीआर 940: 1958 एससीसी ऑनलाइन एससी 95; चरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2004] 2 एससीआर 925: (2004) 4 एससीसी 205; मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य [1962] पूरक 3 एससीआर 848: एआईआर 1963 एससी 174; मसाल्टी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 8 एससीआर 133: 1964 एससीसी ऑनलाइन एससी 30; मुथु नायकर बनाम टी.एन. राज्य (1978) 4 एससीसी 385; शोरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1991) पूरक 2 एससीसी 437; अकबर शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [2009] 7 एससीआर 518 : (2009) 7 एससीसी 415; मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 390; बालू सुदाम खाल्दे एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2023] 6 एससीआर 851: (2023) 13 एससीसी 365; अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2010] 13 एससीआर 311: (2010) 10 एससीसी 259; बालाका सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य [1975] पूरक 1 एससीआर 129 : (1975) 4 एससीसी 511; रमाकांत राय बनाम मदन राय [2003] पूरक 4 एससीआर 17 : (2003) 12 एससीसी 395; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनाती रामुलु एवं अन्य (1994) पूरक 1 एससीसी 590; रणबीर यादव बनाम बिहार राज्य [1995] 2 एससीआर 826: (1995) 4 एससीसी 392 - पर भरोसा किया गया।

श्याम बाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2012] 8 एससीआर 255: (2012) 8 एससीसी 651; कन्हैया लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य [2013] 6 एससीआर 361: (2013) 5 एससीसी 655; सुबल घोराई एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2013) 4 एससीसी 607; मूसा खान बनाम महाराष्ट्र राज्य (1977) 1 एससीसी 733; रणवीर सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2023] 1 एससीआर 841: (2023) 14 एससीसी 41; जॉय देवराज बनाम केरल राज्य (2024) 8 एससीसी 102; बिकाऊ पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [2003] पूरक 6 एससीआर 201: (2003) 12 एससीसी 616; वसंत उर्फ गिरीश अकबरसब सनावाले

बनाम कर्नाटक राज्य [2025] 3 एससीआर 158: 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 337 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

भारतीय दंड संहिता की धारा 149; भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की व्याख्या; गैरकानूनी सभा; निर्दोष दर्शक; गैरकानूनी सभा का सदस्य; गैरकानूनी सभा के सदस्यों को दोषी ठहराने में विवेक का नियम; नेत्र साक्ष्य; चिकित्सा साक्ष्य; सामान्य उद्देश्य; घायल चश्मदीद गवाह का मूल्यांकन; ठोस सामग्री; विश्वसनीय सामग्री

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 1187/2014

सीआरएलए सं. 202/1990 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 17.07.2013 के निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील सं. 1188/2014 के साथ

पक्षकारों की और से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता:

अश्विनी कुमार सिंह, रउफ रहीम, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष अंशुमन, चंदन मालव, सुश्री प्रेरणा सिंह, अंबर कमरुद्दीन, तेजस्वी कुमार, श्रीमती एम. कमरुद्दीन

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता:

दिव्यांश मिश्रा, योषित जैन, मनीष कुमार, सुश्री हिमानी चौधरी, समीर अली खान, प्रांजल शर्मा, अनिल कुमार वर्मा

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति

व्याख्या की सुविधा के लिए, इस निर्णय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है:

सूचकांक [†]

I.	अभियोजन पक्ष का मामला	2
क.	अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य	11
ख.	विचारण न्यायालय का निर्णय	20
II.	आक्षेपित निर्णय	28
III.	अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ	31
IV.	उत्तरदाता-राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ	36
V.	विक्षेपण	39
अ.	भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की व्याख्या.....	40
क.	निर्दोष दर्शक बनाम गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य.....	47
i.	गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों को दोषी ठहराने में विवेक का नियम	48
ख.	गवाहों के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित विधि के सिद्धांत.....	58
i.	प्रत्यक्षदर्शी विवरण और चिकित्सा साक्ष्य के बीच विरोधाभास..	62
ग.	क्या अभियोजन पक्ष के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अपना मामला उचित संदेह से परे साबित कर दिया है?	67
ब.	क्या अभियोजन साक्षी-20 के बयान को प्राथमिकी माना जा सकता था?	69
VI.	निष्कर्ष	74

[†]संपादकीय टिप्पणी : पृष्ठांकन मूल निर्णय के अनुसार है।

1. चूंकि दोनों अपीलों में उठाए गए मुद्दे एक जैसे हैं, अपीलकर्ता सह-दोषी हैं और चुनौती भी उच्च न्यायालय द्वारा पारित उसी निर्णय और आदेश को दी गई है, इसलिए उन पर समान रूप से सुनवाई की गई और इस साझा निर्णय और आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।
2. ये अपीलें पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.07.2013 को आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 202/1990 (इसके बाद, 'आक्षेपित निर्णय') में पारित साझा निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने यहां अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार सत्र वाद सं. 124/1989 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की, जिसमें यहां अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'भा. दं. सं.') की धारा 149 के साथ धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया था।

I. अभियोजन पक्ष का मामला

3. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि जाँच अधिकारी ने घायल प्रत्यक्षदर्शी जगदीश महतो (अभियोजन साक्षी-20) का बयान दिनांक 20.11.1988 को अस्पताल में भर्ती रहते हुए दर्ज किया था, जिसे बाद में प्राथमिकी (प्रदर्श. 7) के रूप में दर्ज किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा दिनांक 20.11.1988 को दर्ज अभियोजन साक्षी-20 का बयान इस प्रकार है:

“एसटी सं. 124/89

5055

16.2.90

जगदीश महतो, पिता-जामुन महतो, निवासी-रहरखाल, थाना-आजमनगर, जिला-कटिहार का बयान आजमनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक एस.आई. ए के झा द्वारा दिनांक: 20.11.88, समय: 13.30 बजे राज्य औषधालय, आजमनगर में दर्ज किया गया।

मेरा नाम जगदीश महतो, पिता-जामुन महतो, निवासी-बहरखाल, थाना-आजम नगर, जिला-कटिहार है। आज दिनांक 20.11.88 को लगभग 13.30 बजे, मैं घायल अवस्था में, सरकारी अस्पताल, आजम नगर में, थाना निरीक्षक, आजम नगर को

अपना बयान देता हूँ कि आज सुबह लगभग 8 बजे, मैं अपने भाई मेघू महतो के साथ अपने खेत की रखवाली कर रहा था जहाँ भैंसें चरा करती थीं। भैंस को वहाँ न देखकर, हम दोनों भाई असलम के खेत में गए, जिस पर मैंने बटाई का काम लिया है और शकरकंद की खेती कर रहा हूँ, और अपने धान के खेत में आकर बैठ गए।

कल, 19.11.88 को, मैंने बिहार सरकार द्वारा मुझे दी गई ज़मीन से मजदूरों द्वारा धान कटवाया था। मैंने उक्त ज़मीन पर खेती की थी। इस कारण श्री जैनुल सरकार, मुस्लिम सरपंच, बारीक, आफ़ताब, सभी निवासी- महिला 400-500 लोगों के साथ वहाँ छिपे हुए थे। वे सभी बंदूक, देसी पिस्तौल, भाला, फरसा, गड़ासा, तलवार, सूली और कचिया आदि से लैस थे। उनमें से कुछ के पास पत्थर थे। उनमें से कुछ बिहार सरकार द्वारा दी गई ज़मीन से धान काट रहे थे। मुझे और मेरे भाई को देखकर, वे सभी चारों तरफ से हमारी ओर दौड़े और हमें घेर लिया। पहले उन्होंने पत्थर फेंके। उनमें से मैंने 1. मसियाद, पिता-माही, 2. आजम, पिता-शेख नौसाद, 3. ख्वाजा, पिता-शेख नौसाद, 4. शेख अलादी, पिता-शेख सादिक, 5. शेख करीम, पिता-सेख सादिक, 6. कैमुद्दीन, पिता-शेख हबीब, 7. साहेबुद्दीन, पिता-हबीब, 8. होदा, पिता-हबीब, सभी का निवास- महिला, 9. मनोरिया, पिता- अज्ञात, 10. असरुल, पिता-झगरू, 11. रज्जाक, पिता- सलीम, 12. सिकंदर, पिता-सलीम, 13. अकु, 14. सल्लू, सभी के पिता-गफ़ूर, 15. इसराइल मुंसी, पिता-शेख कालू, 16. शेख मुस्लिम, 17. शेख बारिक, 18. शेख जैनुल, 19. शेख मुस्तफा, 20. शेख आफ़ताब, सभी के पिता-कलीमुद्दीन, 21. अब्बू नासिर, पिता- बसीर, 22. हकलू, पिता- बाजरू, 23. गुलाम, पिता- हकलू, 24. जैना, पिता- शेख मल्लू, 25. शेख महसुद्दीन, पिता- मस्सू, 26. नियाजुद्दीन, पिता- शेख मसू, 27. इस्माइल, पिता- शेख चुथारू, 28. मसियाद, पिता- शेख मोहिदी, 29. शेख उधवा, पिता-शेख मोहिदी, सभी का निवास - महिला, थाना-आजम नगर हैं, को देखा। इनमें से मनोरिया के हाथ में श्री-नाँट पिस्तौल, अबू नसर के हाथ में बंदूक, गुलाम के हाथ में सूली और अन्य के हाथ में लाठी, भाला, फरसा, गड़ासा, तलवार, सूली और पत्थर थे। पहले तो उन लोगों ने हमें घेर लिया और हम पर पत्थर फेंके। फिर मैंने और मेरे भाई ने शोर मचाया और भागने की कोशिश की। इसी दौरान मुझे एक पत्थर लगा। जब हम गिर पड़े, तो गुलाम ने मेरी पसलियों में सूली से वार किया। फिर उन्होंने हम पर लाठी और फरसा से हमला किया। तभी मेरा भाई मेघू भाग गया, तभी उन लोगों के साथ मौजूद 30. इब्राहिम, पिता- अज्ञात, निवासी- कंटाकोश, थाना- मनिहारी ने पिस्तौल से मेरे भाई मेघू पर

गोली चला दी। फिर वह गिर पड़ा। तब तक हमारा शोर सुनकर गांव के लोग, दूधनाथ महतो पिता- भुनेश्वर महतो, फैजू महतो पिता- जगदेव महतो, श्रीपति महतो पिता- भुजंगी महतो, दासु महतो पिता- राम गोविंद महतो, सरजुग महतो पिता- मुन्नी लाल महतो, सभी का निवास- बहरखाल दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके पीछे बड़ी सं. में पुरुष और महिलाएं भी दौड़ते हुए वहां आए। उन लोगों ने उन पर भी हमला किया। उनमें से सरजुग महतो को भी गोली लगी और उसने दम तोड़ दिया। मेरे भाई मेघू को भी गोली लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। अन्य घायल व्यक्ति दूधनाथ, फैजू, श्रीपति और दासू ने मुझे बताया कि 31. अलाउद्दीन, पिता- आलम, 32. अब्बास, 33. सफात, दोनों के पिता- नसीर, 34. बसीर, 35. फूली, पिता- बलाल, 36. हक्कीमुल, पिता- सुलेमान, 37. महताब, पिता- हकीमुद्दीन, 38. खलील, पिता- जमाल, 39. सतार, पिता- तस्लीम, 40. मिस्टर, पिता- गरीबुल, 41. मटरू, 42. मोतिया, 43. ओसी मोहम्मद, पिता- अलीमुद्दीन, 44. निजाम, 45. इशाक, दोनों के पिता- बदरुद्दीन, 46. सकूर अहमद, 47. हबीब, दोनों के पिता- मेहदी, 48. डेलू, 49. डबलू, दोनों के पिता-सिराज, 50. निजाम, पिता-मोदी खलील, 51. कलीमुद्दीन, पिता-सरफैली, 52. मौजिया, पिता-कलीमुद्दीन, 53. महमुद्दीज, पिता- सफर अली, 54. अलाउद्दीन, पिता-सादी महाजन, 55. साहा, 56. जमाल, दोनों के पिता- बसरत, 57. मुस्तफा, 58. फजाक, 59. इमामदी, 60. फैजुद्दीन, सभी के पिता- बांका नसीर, 61. पछारू, पिता- हनीफ, 62. नजीम, 63. जबिर, पिता- नौशाद, 64. आरिफ, 65. मजीबुल, 66. जमीर, पिता- मकबूल, 67. अयूब, पिता- मकबूल, 68. फारूक, पिता- झगरू, 69. असरुल, पिता- झगरू, 70. असलम, पिता- अलम, 71. मोख्तियार, पिता- ज्ञात नहीं, सभी निवासी-महिला, थाना-आजम नगर, जिला-कटिहार हैं और मुल्ला मास्टर का सहयोगी, जिसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं, भी भाला, फरसा, गड़ासा, तलवार, सुली, कचिया, पत्थर, बंदूक, पिस्तौल से लैस थे। उन्होंने उन्हें घेर लिया था और घायल कर दिया था। कैमुद्दीन ने सरजुग महतो पर पिस्तौल से गोली चलाई थी और उसकी तुरंत मौत हो गई थी। सरजुग महतो और मेघू महतो के घायल होने के बाद, वे लोग उनके शवों को घसीटकर ले गए थे। लेकिन तटबंध के पास अन्य पुरुषों और महिलाओं को देखकर, उन्होंने उन्हें वहीं छोड़ दिया और श्रीपति महतो को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे महिला तटबंध के पास छोड़ दिया था। यह घटना गाँव के सभी पुरुषों और महिलाओं ने देखी थी। वे घटना के बारे में बताएंगे। वे आरोपियों की पहचान करेंगे। घायल व्यक्ति बताएंगे कि

उन्हें किसने घायल किया था। उन लोगों के घटनास्थल से चले जाने के बाद, सह-ग्रामीण हमें और मृतक सरजुग महतो और मेघू महतो को एक खाट पर सरकारी अस्पताल ले गए, जहाँ हमारा इलाज चल रहा है।

यह मेरा बयान है। मेरा दावा है कि उपरोक्त आरोपीगण हमें मारने की नीयत से भाला, फरसा, गड़ासा, तलवार, सूली, कचिया, पत्थर, बंदूक और देशी पिस्तौल से लैस होकर खेत में छिपे हुए थे और उन्होंने सरजुग महतो और मेघू महतो की हत्या कर दी और हमें घायल कर दिया।

मेरा यह बयान मुझे पढ़कर सुनाया गया, जो मुझे सही लगा और मैंने इस पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया।

गवाह:

1. राम सूरज महतो
2. उत्तम महतो
3. सुरेश महतो

आर. टी. आई

जगदीश महतो

सूचना देने वाले के इस कथन को उन्हें पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होंने सही पाया और इस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया।

एसटी/124

हस्ताक्षरित//अरविन्द

आजम नगर थाना

20.11.88"

4. उपरोक्त बयान को बाद में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 154 के तहत निर्धारित प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया और इसे कठियार के आजम नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी सं. 148/1988 के रूप में क्रमांकित किया गया। प्राथमिकी में कुल 72 लोगों को आरोपी बनाया गया था। प्राथमिकी इस प्रकार है:

"मामले और अपराध के संक्षिप्त तथ्य, धाराएं और चोरी की गई संपत्ति का विवरण:

गैरकानूनी रूप से एकत्रित होकर हत्या करने और दूसरों को घायल करने के इरादे से

लाठी, भाला, फरसा, गड़ासा, तलवार, सूली, कचिया, पत्थर, बंदूक, पिस्तौल से हमला, भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/342/302/324/323 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराध किया गया।”

5. प्राथमिकी के अनुसार, घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, प्रथम सूचक, जगदीश महतो (अभियोजन साक्षी-20) ने 20.11.1988 को अपने भाई (मृतक) के साथ अपने कृषि क्षेत्र का दौरा करने का फैसला किया। एक दिन पहले, यानी 19.11.1988 को, उन्होंने उस खेत से धान की फसल काट ली थी जो उन्हें सरकार द्वारा सौंपा गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी सं. 2, 16, 17 और 21 क्रमशः 400-500 व्यक्तियों के साथ हथियारों के साथ अभियोजन साक्षी-20 के कृषि क्षेत्र के पास छिपे हुए थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि अभियोजन साक्षी-20 धान की कटाई करे। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उनमें से कुछ लोगों ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इन सभी लोगों ने अभियोजन साक्षी-20 और उसके भाई को देखकर उन्हें घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया।
6. अस्पताल में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज कराए गए बयान में अभियोजन साक्षी-20 ने 30 लोगों को आरोपी बनाया है। उनके अनुसार, प्राथमिकी में नामजद आरोपी सं. 9 के हाथ में पिस्तौल थी, प्राथमिकी में नामजद आरोपी सं. 21 के हाथ में बंदूक थी, प्राथमिकी में नामजद आरोपी सं. 23 के हाथ में सूली थी और अन्य के पास लाठी, भाला, फरसा, गंडासा, तलवार, सूली, पत्थर आदि हथियार थे। आरोप है कि आरोपियों ने अभियोजन साक्षी-20 पर हमला किया और इस घटना में उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोर सुनकर, अभियोजन साक्षी 3, 4, 5, 6 और 10 क्रमशः सरजुग महतो (मृतक) नामक व्यक्ति और अन्य ग्रामीणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। कहा जाता है कि आरोपियों ने उपरोक्त गवाहों पर भी हमला किया। सरजुग महतो की आरोपी सं. 1 ने गोली मारकर हत्या कर दी।
7. उपर्युक्त प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू हुई। जाँच पूरी होने पर, 24 आरोपियों के विरुद्ध क्रमशः भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 307 और 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया।
8. दंडाधिकारी द्वारा यह आपराधिक मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अंतर्गत सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। इसे सत्र न्यायाधीश, जिला कटिहार के न्यायालय में सत्र वाद सं. 124/1989 के रूप में पंजीकृत किया गया।

9. विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अपराधों के लिए आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय करने की कार्यवाही शुरू की। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

10. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित 24 गवाहों से पूछताछ की:

क्र. सं.	अभियोजन साक्षी	विवरण
1.	सुरज महतो	बहरखाल के निवासी।
2.	राम सूरत महतो	अभियोजन साक्षी-24 द्वारा तैयार शव परीक्षण प्रतिवेदन के गवाह।
3.	दासु महतो	घायल प्रत्यक्षदर्शी; अभियोजन साक्षी-20 के चचेरे भाई।
4.	छेदी महतो	घायल प्रत्यक्षदर्शी।
5.	फैजु महतो	घायल प्रत्यक्षदर्शी।
6.	श्रीपति महतो	घायल प्रत्यक्षदर्शी।
7.	मुनीलाल महतो	मृतक सरजुग के पिता, बहरखाल के निवासी।
8.	चिंता देवी	मृतक सरजुग की पत्नी, बहरखाल की निवासी।
9.	राम नाथ महतो	जब्तू सूची के गवाह, बहरखाल के निवासी।
10.	दूध नाथ महतो	घायल प्रत्यक्षदर्शी।
11.	महारानिया देवी	मृतक मेघु की पत्नी, बहरखाल की निवासी।
12.	तिलकी देवी	अभियोजन साक्षी-5 की पत्नी, बहरखाल की निवासी।
13.	समुद्री देवी	अभियोजन साक्षी-6 की पत्नी, बहरखाल की निवासी।
14.	तुसिया देवी	अभियोजन साक्षी-20 की पत्नी, बहरखाल की निवासी।
15.	भुवनेश्वर महतो	अभियोजन साक्षी-10 के पिता, बहरखाल के निवासी।
16.	सुरेश महतो	अभियोजन साक्षी-6 के भाई, बहरखाल के निवासी।
17.	उत्तम महतो	अभियोजन साक्षी-24 द्वारा तैयार शव परीक्षण प्रतिवेदन के गवाह।
18.	राधे महतो	जब्तू सूची के गवाह; मृतक सरजुग के चचेरे भाई।
19.	अर्जुन महतो	जब्तू सूची के गवाह।
20.	जगदीश महतो	घायल प्रत्यक्षदर्शी; मृतक मेघु के भाई; बहरखाल के निवासी।
21.	डॉ. बी.पी. गुप्ता	किशनगंज अस्पताल में मृतक सरजू एवं मेघु के शव का शव परीक्षण किया।
22.	डॉ. नारायण मिश्रा	आजम नगर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी; 5 घायलों की चोटों की जाँच की।
23.	अरविंद कुमार	अनुसंधानकर्ता अधिकारी।
24.	सुरेंद्र प्रसाद सिंह	सहायक उप-निरीक्षक, आजमनगर थाना; शव परीक्षण प्रतिवेदन तैयार की।

11. इसमें कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों का भी सहारा लिया गया।

प्रदर्श	विवरण
प्रदर्श. 2 से 2/4	बिहार राज्य द्वारा दिए गए परचा।
प्रदर्श. 3 और 3/1	पी.ओ. भूमि का किराया रसीद।
प्रदर्श. 4	फर्दबयान
प्रदर्श. 5 और 5/1	मृतकों की शव परीक्षण प्रतिवेदन।
प्रदर्श. 6 से 6/4	चोटों की प्रतिवेदन।
प्रदर्श. 7	विधिवत प्राथमिकी।
प्रदर्श. 8 से 8/4	पुलिस द्वारा तैयार चोटों की प्रतिवेदन।
प्रदर्श. 9 और 9/1	शव परीक्षण प्रतिवेदन।
प्रदर्श. 10 और 10/1	जब्ती सूची।

12. मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों के आगे के बयान दर्ज किए। आरोपियों ने कहा कि वे सभी निर्दोष हैं और उन्हें इस अपराध में झूठा फंसाया गया है।
13. विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर 21 आरोपियों को कथित अपराध का दोषी ठहराया, जबकि शेष 3 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। सभी दोषी आरोपियों को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
14. अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने मौखिक और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया और इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की।

15. उपर्युक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्ता वर्तमान अपीलों के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

क. अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य

16. मृतक मेघू महतो के भाई जगदीश महतो (अभियोजन साक्षी-20), जिनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक, ने बयान दिया कि सुबह लगभग 8 बजे, अभियोजन साक्षी-20 और मृतक अपने धान के खेत देखने गए थे। इसके बाद, वे शकरकंद के खेत में गए जहाँ उन्होंने क्रमशः आरोपी सं. 17, 2, 21 और 16 को बस्ती की ज़मीन के आसपास घूमते देखा। गवाह ने आगे बयान दिया कि कुछ दूरी पर, उसने 400-500 लोगों को देखा, जो सभी बंदूक, पिस्तौल, सुली, कुदाल, भाला, दरांती आदि हथियारों से लैस थे।
17. गवाह ने आगे बताया कि 400-500 लोगों में से 10-11 लोगों ने उसके खेत से धान काटना शुरू कर दिया और जब मृतक और गवाह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने उन पर पथराव शुरू कर दिया। अभियोजन साक्षी-20 ने क्रमशः आरोपी सं. 9, 4, अलादी (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं), आरोपी सं. 20, 5, 22, 8, 6, 1, 18, 11, 10, 12, अब्बास (प्राथमिकी में आरोपी सं. 32), सफाक (प्राथमिकी में आरोपी सं. 33), नयाजुद्दीन (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं), जहरुद्दीन (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं), इस्माइल (प्राथमिकी में आरोपी सं. 27), आरोपी सं. 2, 17, 21 और गुलाम (प्राथमिकी में आरोपी सं. 23) की पहचान की। उसने बयान दिया कि पत्थर लगने से वह गिर पड़ा। इसके बाद, गुलाम ने उसकी पसलियों पर सूली से वार किया, आरोपी सं. 10 ने उसके सिर पर कुदाल से वार किया, आरोपी सं. 12 ने लाठी से, आरोपी सं. 2 ने गंडासे से और आरोपी सं. 11 ने बाना से हमला किया। अभियोजन साक्षी 20 के अनुसार, उसके भाई के साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान अभियोजन साक्षी 3, 5, 6, 10 और मृतक सरजुग महतो क्रमशः घटनास्थल पर पहुँचे, लेकिन उन पर भी उन लोगों ने हमला किया।
18. अभियोजन साक्षी-20 ने आगे बताया कि उसके भाई की गोली मारकर हत्या की गई और उस पर सूली से भी हमला किया गया। हमले के बाद, सभी आरोपी भाग गए। इसके बाद, ग्रामीण उन्हें आजमनगर अस्पताल ले गए। पुलिस निरीक्षक ने उसका बयान दर्ज किया और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। उसने बताया कि घटना से पहले, बस्ती की

ज़मीन को लेकर उसका महिला गाँव के निवासियों से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। उसने आगे बताया कि आरोपियों का बस्ती की ज़मीन से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। गाँव महिला के एक हाकिमुल ने फेकन महतो के घर में आग लगा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त विवाद के कारण एक हत्या हो गई थी।

19. अभियोजन साक्षी-20 ने स्वीकार किया कि आरोपियों का बस्ती की ज़मीन पर कभी कब्ज़ा नहीं था। उसने पुलिस के सामने यह कहने से इनकार किया कि आरोपी घटना से एक दिन पहले हुई धान की कटाई के कारण उत्तेजित होकर छिपे हुए थे। उसने गवाही दी कि वह धान की फ़सल काट रहे व्यक्तियों को पहचानने में असमर्थ था और उनकी पहचान मज़दूरों के रूप में की। उसके अनुसार, हमले के बाद वह बेहोश हो गया और यह गवाही देने में असमर्थ रहा कि मृतक सरजुग और अभियोजन साक्षी 3, 6 और 10 पर क्रमशः किसने हमला किया था। उसने कहा कि उसे याद नहीं आ रहा कि उसने किनके नाम बताए थे। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि घायल व्यक्तियों ने पुलिस के सामने बताया था कि उन पर किसने हमला किया था। अपनी प्रतिपरीक्षण में, गवाह अपने पिछले बयान से आंशिक रूप से मुकर गया और कहा कि उसे याद नहीं आ रहा कि अस्पताल में उसने पुलिस को जो बयान दिया था, उसे उसे पढ़कर सुनाया गया था या नहीं।

20. अभियोजन साक्षी-20 की चिकित्सीय जांच से पता चला कि उस पर निम्नलिखित चोटें थीं:

- i. दाहिनी ओर की खोपड़ी पर 1" x 1/4" x हड्डी जितनी गहरी चीरा हुआ घाव;
- ii. खोपड़ी पर 2½" x 1/2" x हड्डी जितनी गहरी चीरा हुआ घाव;
- iii. पीठ के दाहिने ओर ¼" व्यास x ½" गहरा छिद्रित घाव;
- iv. दाहिनी जांघ पर 2½ x ½" का एक खरोंच;
- v. बाईं कलाई के जोड़ पर 1½" x 1½" का खरोंच;
- vi. दाहिनी कलाई के जोड़ पर 1" x 1½" का खरोंच;
- vii. बाईं ओर की छाती पर 3" x ½" का खरोंच

21. दासु महतो (अभियोजन साक्षी-3), अभियोजन साक्षी-20 का चचेरा भाई और घटना का एक चश्मदीद गवाह, ने बयान दिया कि अभियोजन साक्षी-20 और उसका भाई (मृतक मेघू महतो) धान के खेत में गए थे। जब उसने चीखें सुनीं, तो वह खेत की ओर भागा। उसके पीछे मृतक सरजुग और क्रमशः अभियोजन साक्षी 5, 6 और 10 आए। उसने बयान दिया कि आरोपी सं. 12 ने उसके सिर पर लाठी से हमला किया, आरोपी सं. 10 ने उसके पैर पर गंडासे से हमला किया, आरोपी सं. 2 और 17 क्रमशः बंदूक पकड़े हुए थे, आरोपी सं. 2 भाला पकड़े हुए था, आरोपी सं. 11 सूली पकड़े हुए था। क्रमशः अभियोजन साक्षी 5, 6, 10 और 20 घायल हो गए। आरोपियों ने क्रमशः सरजुग और मेघू की हत्या कर दी।
22. गवाह ने आगे गवाही दी कि धान की फसल काटने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसने बताया कि वह अपने घर पर था जब उसने दो गोलियों की आवाज़ सुनी। मारपीट के बाद वह बेहोश हो गया और कुछ देर बाद ही होश में आया। उसने आगे गवाही दी कि पुलिस सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच पहुँची थी और उसने अपना संक्षिप्त बयान दिया था। उसने गवाही दी कि उसने अभियोजन साक्षी 20 को 72 आरोपियों में से 40 आरोपियों के नाम नहीं बताए थे, और उसे याद नहीं है कि आरोपी सं. 2 भाले से लैस था और आरोपी सं. 11 सूली से लैस था।
23. अभियोजन साक्षी-3 की चिकित्सीय जाँच से पता चला कि उस पर निम्नलिखित चोटें थीं:
- माथे पर $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times$ हड्डी तक गहरा एक घाव;
 - बाएँ कंधे के ब्लेड के क्षेत्र पर $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ का एक खरोंच;
 - बाएँ जाँघ के बाहरी हिस्से पर $3'' \times \frac{1}{2}''$ का एक खरोंच;
 - बाएँ घुटने के जोड़ के बाहरी हिस्से पर $2'' \times \frac{1}{2}''$ का एक खरोंच
24. फैजू महतो (अभियोजन साक्षी-5), जो घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक है, ने अपने बयान में कहा कि जब उसने बस्ती के दक्षिणी भाग से कुछ शोर सुना, तो वह उस दिशा में दौड़ा। अभियोजन साक्षी-3 उससे आगे-आगे दौड़ रहा था। अभियोजन साक्षी सं. 6, 20 तथा मृतक सरजू और मेघु भी वहाँ उपस्थित थे। घटना-स्थल पर पहुँचने पर गाँव महिला के निवासियों ने उन्हें घेर लिया और अभियुक्त सं. 5 ने फरसा से उसके

दाहिने हाथ पर प्रहार किया तथा सैयाब (फरार अभियुक्त) ने कुदाल से उसके सिर पर प्रहार किया। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त सं. 6, 8 और 22 ने क्रमशः लाठियों से उस पर हमला किया। इसके बाद, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें पता चला कि हमलावरों ने सरजुग और मेघू की हत्या कर दी है, और आरोपी सं. 3, 6 और 20 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोपी सं. 5 ने दो राउंड गोलीबारी की आवाज़ सुनी थी।

25. प्रतिपरीक्षण के दौरान, अभियोजन साक्षी-5 ने गवाही दी कि अस्पताल जाते समय नाव में उसे होश आ गया था। सभी पाँचों घायलों को पुलिस थाने ले जाया गया। वे लगभग सुबह 9 बजे थाने पहुँचे जहाँ पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। इसके बाद, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात में, उप-निरीक्षक ने उसका बयान दर्ज किया था।

26. अभियोजन साक्षी-5 की चिकित्सीय जाँच से पता चला कि उस पर निम्नलिखित चोटें थीं:

- i. दाहिने अग्रबाहु पर $2\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}'' \times$ मांसपेशी गहराई का एक घाव;
- ii. खोपड़ी के मध्य भाग पर $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$ हड्डी गहराई का घाव।

27. घटना के प्रत्यक्षदर्शियों में से एक, श्रीपति महतो (अभियोजन साक्षी-6) ने गवाही दी कि घटना सुबह लगभग 8:30 बजे हुई थी। उसने बस्ती की ज़मीन की दिशा से शोरगुल की आवाज़ सुनी। वह अभियोजन साक्षी-3 के पीछे दौड़ा और अभियोजन साक्षी 5 व 10 क्रमशः उसके साथ दौड़े। गवाह ने गवाही दी कि बस्ती की ज़मीन पर पहुँचने से पहले ही, महिला गाँव के निवासियों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपी सं. 19 ने उसे कुदाल से मारा, आरोपी सं. 14 ने उस पर तलवार से हमला किया और आरोपी सं. 18, 7, 3, 13, मटरू (फरार) और जमशेद (फरार) ने उस पर लाठी से हमला किया। गवाह ने पुलिस के सामने यह कहने से इनकार किया कि उसने बस्ती की ज़मीन की दिशा से शोरगुल की आवाज़ सुनी थी। वह शाम 5 बजे अस्पताल पहुँच गया था, लेकिन उस दिन उसका बयान दर्ज नहीं किया गया।

28. अभियोजन साक्षी-6 की चिकित्सा जाँच से पता चला कि उस पर निम्नलिखित चोटें थीं:

- i. दाहिनी अनामिका उंगली की जड़ पर $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}'' \times$ हड्डी गहरा एक कटा हुआ घाव;
- ii. चोट सं. 1 के दाहिनी ओर $1'' \times \frac{1}{4}''$ गहरा कटा हुआ घाव;
- iii. दाहिनी मध्यमा उंगली पर $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{6}'' \times$ मांसपेशी गहरा कटा हुआ घाव;
- iv. खोपड़ी के दाहिनी ओर $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ का एक कटा हुआ घाव;
- v. दाहिने गाल पर $1''$ व्यास का एक खरोंच;
- vi. बायीं बांह पर $1\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{2}''$ त्रिज्या की हड्डी से बाहर एक कटा हुआ घाव।

29. घटना के चश्मदीद गवाहों में से एक, दूधनाथ महतो (अभियोजन साक्षी-10) ने गवाही दी कि घटना सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे के बीच हुई। कुछ शोर सुनकर, वह बस्ती की जमीन की ओर भागा। जल्ला (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं) ने उसके सिर पर लाठी से प्रहार किया। इसके बाद, किसी ने उसकी गर्दन पर कुदाल से हमला किया। वह हमलावर को देख नहीं पाया क्योंकि उस पर पीछे से हमला किया गया था। इस मोड़ पर, गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। उसने पुलिस के सामने यह कहने से इनकार किया कि बस्ती की जमीन पर पहुँचने पर, महिला गाँव के निवासियों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला किया गया। इसके बाद, उसने मसियान (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं) का नाम हमलावर के रूप में लिया, जिसने पीछे से उसकी गर्दन पर हमला किया था।
30. इसके अलावा, उसने पुलिस के सामने यह कहने से इनकार किया कि आरोपी सं. 10 ने उसके सिर पर लाठी से हमला किया था, आरोपी सं. 18 और 22 ने उस पर लाठी से हमला किया था, आरोपी सं. 4 ने उसकी कलाई पर कुदाल से हमला किया था, आरोपी सं. 1 पिस्तौल से लैस था, आरोपी सं. 11 और 20 भाले से लैस थे, और आरोपी सं. 8 लाठी से लैस था।
31. अभियोजन साक्षी-10 की चिकित्सीय जाँच में उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:
- i. गर्दन के पिछले हिस्से पर $4'' \times 1'' \times 1\frac{1}{2}''$ (गहरा) का एक घाव, जिसमें गर्दन मुड़ी हुई थी;

- ii. पीठ पर 1" x ¼" x ¼" गहरा एक घाव;
- iii. खोपड़ी के पिछले हिस्से पर 1" x ¼" का एक घाव;
- iv. दाहिनी कलाई के जोड़ पर 1 ¼" x ¼" x मांसपेशी जितना गहरा एक घाव।

32. महिला गाँव निवासी और घटना के चश्मदीद गवाह छेदी महतो (अभियोजन साक्षी-4) ने गवाही दी कि घटना सुबह लगभग 8:00 बजे हुई थी। घटना के समय वह अपने शकरकंद के खेत में था। उसने क्रमशः आरोपी सं. 1 और 18 की पहचान की। उसने पहले बताया कि आरोपी सं. 1 के हाथ में बंदूक थी। फिर उसने बताया कि उसके हाथ में भाला था। उसने गवाही दी कि सभी आपस में लड़ रहे थे। उसने आगे बताया कि आरोपी सं. 1 ने मृतक सरजुग की गोली मारकर हत्या कर दी और क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6, 10 और 20 घायल हो गए। आरोपी सं. 19 के हाथ में गंडासा था, और जमीर (फरार) के हाथ में सूली थी। अपनी प्रतिपरीक्षण में, गवाह ने कहा कि उसे झगड़े के पीछे के कारण का कोई पता नहीं था। उसने आगे कहा कि वहाँ बहुत से लोग थे और यह कहना मुश्किल है कि हमलावर कौन थे और दर्शक कौन थे। पुलिस लगभग 12:00 से 1:00 बजे के बीच पहुँची और उसका बयान मौके पर ही दर्ज किया गया।
33. मृतक सरजुग महतो की पत्नी और घटना की प्रत्यक्षदर्शी गवाह चिंता देवी (अभियोजन साक्षी-8) ने बयान दिया कि वह और उनके पति घटना वाले दिन सुबह फसल बो रहे थे। उस समय, मृतक मेघू ने शोर मचाया। अभियोजन साक्षी-8 अपने पति के साथ उस दिशा में दौड़ी। उसने बयान दिया कि उसके पति को महिला गांव के निवासियों ने घेर लिया था। उसने आरोपी सं. 18 की पहचान की, जिसने आरोपी सं. 1 को बंदूक दी, जिसने बदले में उसके पति पर गोली चला दी। इसके बाद, आरोपी सं. 14 ने उस पर सूली से, आरोपी सं. 11 ने कुदाल से और आरोपी सं. 17 ने सूली से हमला किया। अपनी प्रतिपरीक्षण में, गवाह ने बयान दिया कि वहाँ लगभग 400-500 लोगों की भीड़ थी। कुछ हथियारबंद थे, जबकि कुछ निहत्थे थे। उसने आगे बताया कि थाना प्रभारी घटना के 2 घंटे बाद पहुंचा और उससे पूछताछ की।
34. आजम नगर थाने के प्रभारी अधिकारी अरविंद कुमार झा (अभियोजन साक्षी-23) ने बयान दिया कि घटना वाले दिन दोपहर लगभग 1:25 बजे उन्हें सरकारी अस्पताल से एक ओ.डी. पर्ची मिली। उसी के आधार पर उन्होंने अभियोजन साक्षी-20 का बयान दर्ज किया और उसे प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने

अस्पताल से क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6 और 10 की चोट प्रतिवेदन ली और तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। वह दोपहर 3:20 बजे घटनास्थल, यानी बस्ती की जमीन पर पहुँचे। उन्होंने जमीन पर कई जगहों पर खून और खून से सनी एक लाठी देखी। उन्होंने बस्ती की जमीन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण किया, जो उन्हें क्रमशः मृतक मेघू महतो, लालू महतो, धरमू महतो और अभियोजन साक्षी-20 के संयुक्त नाम पर मिले। 21.11.1988 को उन्होंने क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6, 10 और 15 के बयान दर्ज किये।

35. पुलिस अधिकारी ने आगे गवाही दी कि अभियोजन साक्षी-4 ने कहा था कि आरोपी सं. 17 ने मृतक मेघू के शरीर पर सूली से वार किया, इब्राहिम एक कुदाल से लैस था, किरौरी (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं) तलवार से लैस था, तारा (प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित नहीं) गुप्ती से लैस थी, मनोरिया (प्राथमिकी में आरोपी सं. 9) एक पिस्तौल लेकर आई थी, और कैमुद्दीन ने आरोपी सं. 18 से बंदूक छीन ली और मृतक सरजुग पर गोली चला दी। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-8 ने न तो यह बताया कि आरोपी सं. 14 और 17 ने क्रमशः उसके पति पर सूली से हमला किया था और न ही यह कि आरोपी सं. 11 ने उस पर कुदाल से हमला किया था। उसने हमलावरों के रूप में सरफुल, हमजू, मोजामिल, तुलकू, शकील, फालतू, नासिर, अजीमुद्दीन, इशहाक और छोटीया का नाम लिया था।

ख. विचारण न्यायालय का निर्णय

36. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, सत्र वाद सं. 124/1989 में पारित अपने दिनांक 24.05.1990 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने 21 आरोपियों को कथित अपराध का दोषी ठहराया और शेष 3 आरोपियों को बरी कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में दर्ज निष्कर्षों को सात भागों में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है:-

क. सबसे पहले, हमले के तथ्य पर, यह देखा गया कि अभियोजन साक्षी-21, यानी, शवों का शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने दोनों शवों पर आग्नेयास्त्र की चोट सहित कई चोटें पाई थीं। अभियोजन साक्षी-22 द्वारा दिए गए चोटों के विवरण, जिन्होंने घायल गवाहों की जांच की, पांच घायल व्यक्तियों, यानी क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6, 10 और 20 द्वारा बताए गए हमले के संस्करण को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। चोटें

शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे गर्दन, छाती और सिर पर पाई गई, जो तेज और कठोर कुंद हथियारों के कारण हुईं। वे ऐसी चोटें पहुंचाने के समय हमलावरों के इरादे को दर्शाती हैं। उन्हें पता था कि चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। इसके अलावा, अन्य प्रत्यक्षदर्शियों और आईओ की मौखिक गवाही विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि विभिन्न स्थानों पर खून के निशान, घसीटने के निशान और खून से सनी एक लाठी की मौजूदगी भी अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए गए मामले की पुष्टि करती है। उसने कहा कि दो मौतों और पाँच लोगों के घायल होने के बारे में कोई विवाद नहीं है। उसने माना कि आरोपी सं. 21, 22, 23 और 24 के मौखिक साक्ष्यों से, आरोपी सं. 20 द्वारा बताए गए हमले के तथ्य की पूरी तरह पुष्टि होती है।

ख. उपरोक्त के क्रम में, विचारण न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस कथन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मृतक और गवाह बस्ती की ज़मीन से जबरन धान काटना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने धान काटना शुरू किया, आरोपी सं. 3 और 24 ने क्रमशः विरोध किया, जिसके कारण मृतक और गवाहों ने दोनों आरोपियों पर हमला किया। न्यायालय ने इस आधार पर इस बचाव पक्ष के तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि आरोपियों ने जिस स्थान पर धान काटने का दावा किया था, वहाँ धान नहीं मिला था। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

39. उपरोक्त विभिन्न कंडिकाओं में संदर्भित अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि शवों का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी ने दोनों शवों पर चोटों के अनेक निशान पाए। दोनों शवों पर आग्नेयास्त्र के घाव थे। इस तरह चिकित्सक कथित घटना के चश्मदीदों द्वारा दी गई हमले की तस्वीर का पूरी तरह समर्थन करता है। आजमनगर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, जिन्होंने पांचों घायल व्यक्तियों की जांच की थी, ने जगदीश महतो, दूधनाथ महतो, फैजू महतो, श्रीपति महतो और दासु महतो के शरीर पर भी विभिन्न चोटों के निशान पाए थे। उनकी चोटों से पता चलता है कि शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे गर्दन, छाती, सिर आदि पर धारदार काटने वाले हथियारों और कठोर कुंद पदार्थ से चोटें आईं और चोटें ऐसी थीं कि घातक परिणाम हो सकते थे। ये चोटें हमलावरों के इरादे को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि इन चोटों को पहुंचाने के समय उन्हें बहुत स्पष्ट ज्ञान था डॉक्टर द्वारा पाई

गई ये चोटें पाँचों घायलों जगदीश महतो (अभियोजन साक्षी 20), दासु महतो (अभियोजन साक्षी 3), फैजू महतो (अभियोजन साक्षी 5), श्रीपति महतो (अभियोजन साक्षी 6) और दूध नाथ महतो (अभियोजन साक्षी 10) द्वारा बताई गई हमले की कहानी की पूरी तरह पुष्टि करती हैं। हमले के बिंदु पर अन्य चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि दो डॉक्टरों अभियोजन साक्षी 21 और 22 के चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। आई.ओ. अभियोजन साक्षी 23 और ए.एस.आई. अभियोजन साक्षी 24 ने भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन किया है - उचित चोट प्रतिवेदन (विस्तार 8 शृंखला), जाँच प्रतिवेदन और ज़ब्त सूचियाँ भी कहानी का पूरी तरह समर्थन करती हैं।

इस मामले के जांच अधिकारी (अभियोजन साक्षी 23) द्वारा वर्णित पी.ओ. में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्चा भूमि पी.ओ. का खेत है और घटना लगभग 50 गज के बड़े क्षेत्र में हुई। विभिन्न स्थानों पर खून के निशान, घसीटने के निशान, कुचलने के निशान, ढेला और खून से सने लाठियों की मौजूदगी अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए हमले की तस्वीर की पूरी तरह पुष्टि करती है कि इस हमले में बड़ी सं. में लोग शामिल थे और हमला अंधाधुंध था। जांच अधिकारी के साक्ष्य से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पी.ओ. के पास किसी भी खेत में न तो धान का कोई बंडल था और न ही धान की कटाई हुई थी। अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, भीड़ के कुछ सदस्यों ने पर्चा भूमि से जबरन धान काटना शुरू कर दिया, जिसका शिकायतकर्ता जगदीश महतो और उनके भाई मेघू महतो ने विरोध किया, जिस पर उन्हें भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला किया गया।

इसके विरुद्ध बचाव पक्ष की कहानी के अनुसार, शिकायतकर्ता पक्ष एक समूह में पी.ओ. भूमि से जबरन धान काटने गया था और वे धान काट रहे थे जिसका हबीब और अलाउद्दीन ने विरोध किया जिस पर शिकायतकर्ता पक्ष ने हबीब और अलाउद्दीन पर हमला कर दिया जिससे वे घायल हो गए तब ग्रामीण हबीब और अलाउद्दीन की मदद में आ गए और "मारपीट" हुई। यह विचारणीय है कि हबीब द्वारा दायर शिकायत याचिका में निहित बचाव पक्ष की कहानी घटना के दिन 6-7 बीघा से धान की चोरी के बारे में बताती है। दो हत्याओं और पांच व्यक्तियों के घायल होने का बचाव पक्ष द्वारा गंभीरता से

विवाद नहीं किया गया है। यदि वास्तव में शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा धान की कटाई की गई थी और आरोपी पक्ष द्वारा अपने धान की रक्षा के लिए विरोध किया गया था और संपत्ति की रक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग किया गया था जैसा कि बचाव पक्ष ने तर्क दिया है लेकिन वहां न तो बंडल के आकार में और न ही फैले हुए आकार में कोई धान काटा गया था। यह बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी को झूठा साबित करता है। इस मामले में जांच अधिकारी और जिन दो डॉक्टरों से पूछताछ की गई है, वे स्वतंत्र और जिम्मेदार लोक सेवक हैं। उनके पास आरोपियों के खिलाफ झूठी गवाही देने का कोई कारण नहीं है। उनकी प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई विवाद हो। इसलिए मुझे उनके साक्ष्य की सत्यता पर संदेह करने लायक कुछ भी नहीं लगता। तदनुसार, मैं अभियोजन साक्षी 21, 22, 23 और 24 के रूप में जांचे गए लोक सेवकों के साक्ष्य पर भरोसा करता हूँ। उनके साक्ष्य से, शिकायतकर्ता द्वारा फ़र्ज बयान और साक्ष्य में दी गई हमले की तस्वीर, साथ ही अन्य घायल व्यक्तियों और चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से पूरी तरह पुष्टि होती है।”

ग. दूसरे, विचारण न्यायालय ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बचाव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपियों ने बस्ती की ज़मीन पर धान की खेती नहीं की होगी क्योंकि यह पहले बिहार राज्य के कब्जे में थी, और बाद में अभियोजन साक्षी-20 और उसके भाइयों के पास। न्यायालय ने आरोपियों द्वारा धान उगाए जाने की संभावना को भी खारिज कर दिया क्योंकि किसी भी गवाह या मृतक ने बस्ती की ज़मीन से धान की कटाई नहीं की थी। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“40.[...]इसलिए इस मामले में आरोपियों द्वारा प्रस्तुत दावा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे बिहार राज्य के बसे हुए लोगों को केवल आरोपी पक्ष की ताकत के बल पर बसी हुई भूमि से पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति निजी बचाव के किसी अधिकार का निर्माण नहीं कर सकती, बल्कि यह स्पष्ट रूप से सुझाव देती है कि पूरी घटना "शक्ति ही अधिकार है" के सिद्धांत का परिणाम है। आरोपियों के पास पर्चा दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन वे अपनी हिंसा के बल पर उस भूमि पर कब्जा करने के लिए गए, जिसे शिकायतकर्ता और उसके भाइयों और चचेरे भाइयों ने बसा लिया था। इस प्रकार, मैं पाता हूँ कि निजी बचाव के अधिकार

के लिए तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है।[...]"

- घ. तीसरा, विचारण न्यायालय ने कहा कि गवाहों की गवाही में विरोधाभास आरोपियों के लिए कोई मददगार नहीं होगा क्योंकि यह पाया गया कि गवाहों ने प्रासंगिक तथ्यों को छिपाया नहीं था। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

"42. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बयान से पलट गए गवाहों की मदद से घटना के बिंदु पर मौजूद साक्ष्यों में कुछ विरोधाभास दिखाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे विरोधाभासों का इस्तेमाल बचाव पक्ष के पक्ष में किया जा सकता है, जबकि वाद दैनिकी और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य बताते हैं कि वे प्रासंगिक तथ्यों को नहीं छिपा रहे हैं। मुझे बचाव पक्ष द्वारा बताए गए विरोधाभासों में कोई दम नहीं दिखता। सभी आरोपी (अभियोजन साक्षी) अनपढ़, सीधे-सादे और ग्रामीण हैं। अगर जटिल सवालों के कारण अधिवक्ता उनसे कुछ हासिल कर लेता है, तो उसका इस्तेमाल दूसरे आरोपी (अभियोजन साक्षी) को अनुबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता।[...]"

- ई. चौथा, अभियोजन साक्षी सं. 3, 4, 7, 8 और 20 के मौखिक साक्ष्य क्रमशः विश्वसनीय पाए गए, विशेष रूप से यह तथ्य कि आरोपी सं. 1 ने मृतक सरजुग महतो की हत्या के लिए गोलियां चलाई थीं, आरोपी इब्राहिम ने मृतक मेघू महतो की हत्या के लिए गोलियां चलाई थीं, और भीड़ के अन्य सदस्यों ने उन पर हमला किया था। यह भी उल्लेख किया गया कि गैरकानूनी भीड़ के सदस्यों का एक ही उद्देश्य था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे बिना किसी उकसावे के हथियारों के साथ वहाँ पहुँचे थे।

- च. पाँचवाँ, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोप पूरी तरह साबित हुआ क्योंकि आरोपी चाहते थे कि अभियोजन साक्षी-20 और उसके भाई बस्ती की जमीन पर अपना दावा छोड़ दें ताकि आरोपी उस पर जबरन कब्जा कर सकें। यह माना गया कि गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्यों का सामान्य उद्देश्य अभियोजन साक्षी-20 और उसके भाइयों को बस्ती की जमीन से जबरन बेदखल करने की उनकी अवैध योजना के रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनना था। इसके अलावा, सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप भी क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6, 10 और 20 पर हमले के संबंध में पूरी तरह

साबित हुए। संबंधित टिप्पणियां इस प्रकार हैं:-

“44. प्रश्न सं. ॥: आरोपी सत्यापनकर्ताओं के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि कैमुद्दीन ने सरजुग महतो पर गोली चलाई और इब्राहिम ने मेघू महतो पर गोली चलाई। शवों पर आग्नेयास्त्रों के घावों के अलावा कई अन्य चोटें हैं जो दर्शाती हैं कि भीड़ के कई अन्य सदस्यों ने भी दोनों पर हमला किया था। आरोपी सत्यापनकर्ता 4 छेदी महतो, आरोपी सत्यापनकर्ता 8 चिंता देवी, आरोपी सत्यापनकर्ता 7 मुनिलाल महतो, आरोपी सत्यापनकर्ता 3 दासु महतो और शिकायतकर्ता आरोपी सत्यापनकर्ता 20 के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि कैमुद्दीन ने सरजुग महतो पर गोली चलाई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह भी सिद्ध होता है कि इब्राहिम ने मेघू महतो पर गोली चलाई और भीड़ के अन्य सदस्यों ने भी उस पर हमला किया। यह इब्राहिम इस मामले में फरार हो गया है। इस मामले में इब्राहिम फरार हो गया है। भीड़ के सभी सदस्यों की पूर्व-योजना इस बात से स्पष्ट होती है कि वे विभिन्न हथियारों से लैस होकर वहाँ इकट्ठा हुए थे और बिना किसी उकसावे के उन्होंने शिकायतकर्ता और उसके भाई मेघू महतो पर हमला करना शुरू कर दिया और जो लोग उन्हें बचाने आए, उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया। इससे स्पष्ट है कि सभी का एक ही उद्देश्य था कि शिकायतकर्ता और उसके भाई, जिन्हें ज़मीन के संबंध में पर्चा मिला था, अपना दावा छोड़ दें और आरोपी व्यक्तियों को उस बसाई हुई ज़मीन पर जबरन कब्ज़ा करने दें और अगर कोई विरोध करे तो उन लोगों को मार दिया जाए। इसलिए भीड़ के सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य था कि शिकायतकर्ता पक्ष को बसाई हुई ज़मीन से जबरन बेदखल करने की उनकी अवैध योजना के रास्ते में आने वाले लोगों की मौत हो। इसलिए भीड़ के सभी सदस्य मेघू महतो और सरजुग महतो की मौत के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं। अतः इस हमले में शामिल आरोपियों के विरुद्ध धारा 302/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप सिद्ध होता है। आरोपी असलम, कलीमुद्दीन और अलाउद्दीन के बीच कोई संबंध स्थापित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। अतः वे इस घटना के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। कैमुद्दीन के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप सिद्ध होता है। दूधनाथ महतो, जगदीश महतो, दासु महतो, श्रीपति महतो और

फैजू महतो पर जानलेवा हमले के लिए आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप भी ऊपर वर्णित साक्ष्यों से सिद्ध होता है।[...]

छ. छठा, विचारण न्यायालय ने पाया कि आरोपी सं. 10 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 7 और 20 द्वारा हमलावर के रूप में की गई थी। इसके अलावा, आरोपी सं. 12 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 7, 8, 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 11 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 8, 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 18 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 4, 6, 8, 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 19 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 4, 6, 16 द्वारा की गई; आरोपी सं. 5 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 8 और 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 8 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 5 और 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 22 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 5 और 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 2 की पहचान क्रमशः 3 और 20 द्वारा की गई; आरोपी सं. 14 की पहचान क्रमशः अभियोजन साक्षी 7 और 8 द्वारा की गई; आरोपी सं. 3, 7, 13, 16 की पहचान अभियोजन साक्षी-6 द्वारा की गई; आरोपी सं. अभियोजन साक्षी-20 द्वारा क्रमशः 4, 9, 16, 20 और 21 पर टिप्पणी की गई। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“45. अभियोजन साक्षी की गवाही में मैंने पाया है कि आरोपी अल्लू उर्फ अलाउद्दीन की पहचान अभियोजन साक्षी 3 दासु महतो और शिकायतकर्ता अभियोजन साक्षी 20 जगदीश महतो ने भीड़ में हमलावरों के रूप में की है। इसके अलावा उसका नाम अभियोजन साक्षी 7 मुनीलाल महतो की गवाही में सरजुग महतो के मृत्यु पूर्व बयान के रूप में आया है। आरोपी सल्लू की पहचान अभियोजन साक्षी 3 दासु महतो, अभियोजन साक्षी 8 चिंता देवी, अभियोजन साक्षी 20 जगदीश महतो ने की है और उसका नाम अभियोजन साक्षी 7 की गवाही में भी आया है। आरोपी होदा की पहचान अभियोजन साक्षी 3, अभियोजन साक्षी 8 और अभियोजन साक्षी 20 ने की है। आरोपी समुद्दीन की पहचान अभियोजन साक्षी 4 छेदी महतो, अभियोजन साक्षी 6 श्रीपति महतो, अभियोजन साक्षी 8 चिंता देवी और अभियोजन साक्षी 20 जगदीश महतो ने की है 4, अभियोजन साक्षी 6 और अभियोजन साक्षी 16 सुरेश महतो। आरोपी असरुल की पहचान अभियोजन साक्षी 8 चिंता देवी और अभियोजन साक्षी 20 जगदीश ने की है। आरोपी रजाक की पहचान अभियोजन साक्षी 5 फैजू महतो और अभियोजन साक्षी 20 जगदीश महतो ने की है। आरोपी सिकंदर की पहचान

अभियोजन साक्षी 5 फैजू महतो और अभियोजन साक्षी 20 जगदीश महतो ने की है। आरोपी मुस्लिम सरपंच की पहचान अभियोजन साक्षी 3 दासु महतो और अभियोजन साक्षी 20 जगदीश महतो ने की है। आरोपी उदवा की पहचान अभियोजन साक्षी 6 श्रीपति महतो ने की है। आरोपी माजिया उर्फ मोजिब की पहचान भी अभियोजन साक्षी 6 ने की है। आरोपी मिस्टर की पहचान अभियोजन साक्षी 8 चिंता देवी ने की है और अभियोजन साक्षी 7 ने मृत्यु पूर्व दिए गए अपने बयान में उसका नाम भी लिया है। आरोपी बारीक की पहचान शिकायतकर्ता जगदीश महतो ने की है। आरोपी आफताब, मसियत, आजम और खाजा की पहचान भी शिकायतकर्ता जगदीश महतो अभियोजन साक्षी 20 ने की है। आरोपी हबीब की पहचान अभियोजन साक्षी 6 श्रीपति महतो ने की है। इस तरह इन सभी 21 आरोपियों पर अभियोजन साक्षी बी ने स्पष्ट पहचान के साथ विशेष रूप से आरोप लगाया है कि उन्होंने इस हमले में भाग लिया था।

ज. अंततः, चूँकि अभियोजन पक्ष क्रमशः आरोपी सं. 15, 23 और 24 के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा, इसलिए विचारण न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“44. [...]तदनुसार, मैं पाता हूँ कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी असलम, कलीमुद्दीन और अलाउद्दीन को छोड़कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह की उचित छाया से परे साबित कर दिया है।”

II. आक्षेपित निर्णय

37. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट 18 दोषियों ने आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 202/1990 के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 17.07.2013 के अंतिम निर्णय और आदेश के माध्यम से 7 आरोपियों को बरी करते हुए अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने 11 आरोपियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की। उच्च न्यायालय का यह निर्णय और आदेश तीन भागों में है।

- i. पहला, उच्च न्यायालय ने प्रदर्श 1 श्रृंखला (संबंधित आरोपी पक्ष द्वारा भूमि के निपटान हेतु दायर याचिकाएँ) पर भरोसा करते हुए, यह माना कि बचाव पक्ष ने प्रदर्श 2 श्रृंखला (राज्य सरकार द्वारा आरोपी पक्ष-20 और अन्य के पक्ष में दिया

गया पर्चा) की वैधता को स्वीकार किया है, विशेष रूप से, उसने खाता और खसरा सं. को स्वीकार किया है। इस प्रकार, प्रदर्श 2 श्रृंखला को चुनौती न दिए जाने के कारण निर्णायक कहा जा सकता है। संबंधित टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“52. इस मामले में एक अजीबोगरीब बात है और वह है इसके मूल का मामला। यह मूल विवादित ज़मीन पर वास्तविक भौतिक कब्ज़ा रखने के अधिकार से जुड़ा है। अगर बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष को बिना किसी दबाव के अपनी नाव पर चलने दिया होता, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है, बचाव पक्ष आरोपी पक्ष से प्रतिपरीक्षण के दौरान दिए गए सुझावों से संतुष्ट नहीं था। वे मैदान में कूद पड़े और अपनी दलील पेश की कि जमीन पर उनका कब्ज़ा है और इसके समर्थन में उन्होंने ट्रेस-मैप, सी.एस. खतियान, आर.एस. खतियान प्रदर्शित किए हैं। इतना ही नहीं प्रदर्श-1 से 1/4 तक बचाव पक्ष ने जमीन के निपटारे के लिए संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दायर याचिकाओं को भी अभिलेख पर लाया था और इस तरह की कार्रवाई से बचाव पक्ष ने इसकी औचित्य, वास्तविकता को स्वीकार किया था और इसके कारण बचाव पक्ष ने प्रदर्श-2 श्रृंखला की वैधता को स्वीकार कर लिया था, जो अभियोजन पक्ष के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा दी गई खरीद थी। बचाव पक्ष का यह कहीं भी मामला नहीं है कि उन्होंने प्रदर्श-2 श्रृंखला, पर्चा को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कभी चुनौती दी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि, पूर्वोक्त प्रदर्श-2 की निर्णायकता में स्वीकृति है।

53. जब कोई विशेष कार्य किसी विशिष्ट कानून के आदेश के अनुसरण में किया जाता है, तो उसकी वास्तविकता, औचित्य, प्रभावशीलता और निष्पादन तब तक स्वीकार किए जाएंगे जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए। बचाव पक्ष ने कहीं भी खरीद की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी या खंडन करने की कोशिश नहीं की, और यहां तक कि अभियोजन पक्ष के पक्ष में खरीद जारी होने के बावजूद, जब बचाव पक्ष की ओर से कोई विशिष्ट दावा होता है, तो वे कभी भी साथ-साथ जमीन पर नहीं आए, तो उस स्थिति में इसे कम से कम इस हद तक साबित किया जाना चाहिए था कि प्रदर्श-2 श्रृंखला के तहत लाई गई भूमि पर कब्ज़े से संबंधित अभियोजन पक्ष के संस्करण के संबंध में संदेह पैदा हो, प्रदर्श-2 मेघू महतो से संबंधित है जो

गिद्धौर गांव के खाता सं. 94 के खेसरा सं. 29/3 की 1.25 एकड़ जमीन के बंदोबस्त का खुलासा करता है, 2/1 जगदीश महतो से संबंधित है जो खेसरा सं. 1.50 एकड़ क्षेत्र की सीमा तक है। गिद्धौर गांव के खाता सं. 94 के 29/1, 2/2 धरमु महतो से संबंधित है जो गिद्धौर गांव के खाता सं. 94 के खेसरा सं. 108 (एमआई) के 1 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है, 2/3 दासु महतो से संबंधित है जो गिद्धौर गांव के खाता सं. 94 के खेसरा सं. 29/5 के 1 एकड़ क्षेत्र को कवर करता है, 2/4 लालू महतो से संबंधित है जो गिद्धौर गांव के खाता सं. 94 (एमआई) के खेसरा सं. 29/4 के तहत 1 एकड़ क्षेत्र की सीमा तक है।

xxx

55. कोई भी प्रदर्श, अर्थात् प्रदर्श-एफ शृंखला, प्रदर्श-जी, खाता सं. 94 से संबंधित नहीं है, जो क्रय के अंतर्गत खाता है, न कि प्रदर्श-सी के अंतर्गत दावा किया गया खाता सं. 14। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श-। शृंखला के तहत दायर संबंधित याचिकाओं को प्रदर्शित करके बचाव पक्ष ने वास्तव में खाता सं., खेसरा सं. को स्वीकार करते हुए अपनी स्थिति दर्शाई थी और इस तरह उन्होंने अपने दावे को आगे बढ़ाने या खाता सं. 94 के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में अपना दावा करने की अपनी स्थिति को वस्तुतः समाप्त कर दिया है, खाता अभियोजन पक्ष के पक्ष में आवंटित किया गया है।”

- ii. दूसरे, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि घायल गवाहों, अर्थात् क्रमशः अभियोजन साक्ष्य सं. 3, 5, 6, 10 और 20, की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पाया कि उक्त गवाहों की मौखिक गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई गई। इसके अलावा, **श्याम बाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2012) 8 एससीसी 651** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि गवाहों के मौखिक साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक-दूसरे से संबंधित हैं। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“60. शेष गवाहों की बात करें तो, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1. सी अभियोजन साक्षी, 3, 4, 5, 6 और 20 घायल गवाह हैं जिनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उनकी गवाही को देखने के बाद, यह विश्वसनीय

और भरोसेमंद पाई गई है क्योंकि उनकी गवाही से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने साक्ष्य को किसी भी तरह के घटनाक्रम से जोड़ने की कोशिश नहीं की है या अपनी स्थिति से परे जाकर, जैसा कि उन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में माना है, घटना के दौरान अपीलकर्ताओं के हाथों पीड़ित हुए हैं। उनके साक्ष्य से यह भी पता चला है कि वे अंतर्संबंधित हैं।[...]"

- iii. तीसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता के संबंध में, **कन्हैया लाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य**, (2013) 5 एससीसी 655 में दर्ज, और **सुबल घोराई एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, (2013) 4 एससीसी 607 में दर्ज इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके उच्च न्यायालय ने माना कि सभी आरोपी व्यक्ति गैरकानूनी भीड़ के सदस्य थे और गैरकानूनी भीड़ का सामान्य उद्देश्य कथित अपराध को अंजाम देना था। अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष कुछ आरोपियों के खिलाफ उचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में सक्षम था। ऐसा कहने के बाद, इसने आरोपी सं. 4, 5, 16, 18, 20, 21 और 22 को क्रमशः बरी कर दिया, क्योंकि उनके निष्क्रिय दर्शक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

"75. इस प्रकार, घायल गवाहों सहित, आरोपी गवाहों के साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद, यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। हालाँकि, अपीलकर्ता आजम, असरुल, आफताब आलम, शहाबुद्दीन, मोहम्मद खाजा, बारिक, मोहम्मद सिकंदर को एक गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में अपनी संलिप्तता का पता चला, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से उन पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया और जैसा कि अभियोजन पक्ष ने स्वयं खुलासा किया है कि वहाँ बड़ी सं. में लोग मौजूद थे, तो ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर दर्शक के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता।

76. इसके परिणामस्वरूप, उन्हें कम से कम संदेह का लाभ पाने का हकदार पाया जाना चाहिए और तदनुसार बरी किया जाना चाहिए। वे जमानत पर हैं। इसलिए, उन्हें जमानत बांड के दायित्व से मुक्त करने का निर्देश दिया जाता

है।”

38. उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्ता वर्तमान अपील के साथ हमारे समक्ष उपस्थित हैं।

III. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

39. आपराधिक अपील सं. 1187/2014 में एकमात्र अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रऊफ रहीम ने दलील दी कि अभियोजन साक्षी-20 के बयान के आधार पर दोपहर 2:35 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालाँकि, अन्य गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि अभियोजन साक्षी-20 का बयान पुलिस को दी गई पहली सूचना नहीं थी। उन्होंने दलील दी कि यह अकल्पनीय है कि शिकायतकर्ता अचानक हुए हमले में 72 हमलावरों को देख और पहचान सका। उन्होंने आगे दलील दी कि जहाँ तक आरोपी सं. 17 का संबंध है, विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया।

i. श्री रहीम ने आगे दलील दी कि अभियोजन साक्षी-20 ने आरोपी सं. 2, 10, 11 और 12 को अपने हमलावरों के रूप में नामित किया है। अभियोजन साक्षी-20 ने गवाही दी थी कि आरोपी सं. 17, आरोपी सं. 16 और 21 के साथ क्रमशः बस्ती की जमीन के पास घूम रहा था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों सं. 16 और 21 को मूकदर्शक होने की संभावना के आधार पर बरी कर दिया है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट रूप से अभिलेख में आया है कि महिला गांव के कई निवासियों की जमीन बस्ती की जमीन के उत्तर में स्थित है। इसलिए, उनकी उपस्थिति को असामान्य नहीं कहा जा सकता है। उल्लेखनीय रूप से, आरोपी सं. 17 का आरोपी सं. 1 या 2 से कोई संबंध नहीं है, जो बस्ती की जमीन पर अपना अधिकार जता रहे हैं।

ii. श्री रहीम ने बताया कि अभियोजन साक्षी 5 और 6 क्रमशः आरोपी सं. 17 की उपस्थिति या हमलावर के रूप में पहचान करने में विफल रहे। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी 3 ने अभियोजन साक्षी 23, अर्थात् जाँच अधिकारी, के बयान में दर्ज अपने बयान में सुधार किया है। जाँच अधिकारी ने गवाही दी कि अभियोजन साक्षी 3 ने अपने पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि आरोपी सं. 17 भाले से लैस था।

iii. उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी-3 को विश्वसनीय गवाह नहीं कहा जा सकता क्योंकि अन्य गवाहों, यानी आरोपी-5, 6 और 10 ने न तो आरोपी सं. 17 की उपस्थिति की पहचान की है और न ही यह बताया है कि वह हमलावरों में से एक था, जबकि उन

सभी ने घटनास्थल पर एक साथ पहुँचने की बात कही है। जाँच अधिकारी के बयान से यह भी पता चला कि आरोपी-8 ने उसके सामने यह नहीं बताया था कि आरोपी सं. 17 ने उसके पति पर हमला किया था।

- (iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की प्रयोज्यता के संबंध में, श्री रहीम ने **मूसा खान बनाम महाराष्ट्र राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, (1977) 1 एससीसी 733 में दर्ज, यह प्रस्तुत करने के लिए कि न्यायालयों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी समय भीड़ के पास मौजूद था या किसी भी स्तर पर इसमें शामिल हुआ या चला गया, वह शुरू से अंत तक उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कृत्य का दोषी है। उन्होंने आगे **रणवीर सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, (2023) 14 एससीसी 41 में दर्ज, अपने इस प्रस्तुतीकरण को पुष्ट करने के लिए कि, ऐसे मामलों में, न्यायालयों को सबूतों का अधिक बारीकी से मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि हमेशा दोषी के साथ निर्दोष को फंसाने की प्रवृत्ति होती है। उन्होंने तर्क दिया कि गवाह की मौखिक गवाही को तभी सुसंगत कहा जा सकता है जब सबूत विश्वसनीय पाया जाता है, और न्यायालय की अंतरात्मा को संतुष्ट करता है।
- v. अंत में, श्री रहीम ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों को ठीक से प्रस्तुत न करके एक गंभीर भूल की है। उसने केवल साक्ष्यों का उल्लेख किया है, उनका मूल्यांकन नहीं किया है। उन्होंने दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत साक्ष्यों के अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाए और अपीलकर्ता को बरी किया जाए।
40. आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में नौ अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार सिंह ने तर्क दिया कि प्राथमिकी पूर्व-निर्धारित और बाद में विचारित है। कथित तौर पर यह घटना 20.11.1988 को सुबह लगभग 8 बजे हुई थी। जांच अधिकारी ने लगभग 1:30 बजे सूचनाकर्ता का बयान दर्ज किया और उसी दिन दोपहर 2:35 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई। हालाँकि, इसे संबंधित दंडाधिकारी को 2 दिन बाद प्रेषित किया गया, जैसा कि उक्त प्राथमिकी के कॉलम 8 से स्पष्ट है। इसलिए, प्राथमिकी को अग्रेषित करने में पर्याप्त देरी और उसके स्पष्टीकरण न दिए जाने के कारण, प्राथमिकी संदिग्ध हो जाती है और इसके अतिरिक्त संस्करण होने का संदेह

होगा।

- i. उन्होंने प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्षी-5 ने अपने बयान में कहा है कि वह लगभग सुबह 9 बजे सभी पाँच घायल व्यक्तियों, अर्थात् अभियोजन साक्षी-3, 6, 7, 10 और 20, के साथ थाना पहुँचा। पुलिस उप-निरीक्षक ने घायल व्यक्तियों के कागजात तैयार किए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-3 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उप-निरीक्षक लगभग सुबह 11 बजे अस्पताल पहुँचा, जहाँ उसका बयान दर्ज किया गया। जबकि अभियोजन साक्षी-4 ने बयान दिया कि उप-निरीक्षक लगभग दोपहर 12 बजे घटनास्थल पर पहुँचा, जहाँ उसने अपना बयान दर्ज किया।
- ii. उपरोक्त गवाहों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों के आलोक में, इस संभावना को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि अभियोजन साक्षी-20 का बयान, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद दर्ज किया गया होगा। ऐसी परिस्थितियों में, अभियोजन साक्षी-20 द्वारा दिए गए बयान को प्राथमिकी नहीं माना जा सकता। परिणामस्वरूप, जाँच को दूषित कहा जा सकता है, और ऐसी दूषित जाँच पर भरोसा करना अनुचित होगा।
- iii. उपरोक्त दलील को पुष्ट करने के उद्देश्य से, श्री सिंह ने अभियोजन साक्षी-22, अर्थात् आजम नगर अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी और अभियोजन साक्षी-23, अर्थात् जांच अधिकारी, के बयानों में एक और विरोधाभास को उजागर किया। जांच अधिकारी ने बयान दिया था कि वह अस्पताल से प्राप्त ओ.डी. पर्ची के आधार पर अस्पताल गए थे। जबकि अभियोजन साक्षी-22 ने कहा कि उन्होंने पुलिस के अनुरोध पर घायल व्यक्तियों की चोटों की जाँच की थी। उन्होंने आगे दलील दी कि विचारण न्यायालय के समक्ष गवाहों की गवाही में कुछ महत्वपूर्ण चूक के रूप में विरोधाभास हैं।
- (iv) अंत में, उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों का सही परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया। अभियोजन साक्षी-5 ने गवाही दी थी कि आरोपी सं. 5 ने उसके दाहिने हाथ पर फरसा से प्रहार किया था, और आरोपी सं. 6, 8 और 22 ने क्रमशः उस पर लाठी से हमला किया था। आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने क्रमशः आरोपी सं. 5 और 22 को बरी कर दिया, लेकिन क्रमशः आरोपी सं. 6

और 8 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोपी सं. 6 और 8 के विरुद्ध मामला उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए आरोपियों के मामले के समान ही है।

IV. उत्तरदाता-राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

41. विद्वान अधिवक्ता श्री दिव्यांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि अभिलेखों में उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से हमले में अपीलकर्ताओं की विशिष्ट भूमिका को इंगित करते हैं। वे सभी भारी हथियारों से लैस थे और अपने समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभियोजन पक्ष पर अंधाधुंध हमला किया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता-आरोपी सं. 17 की पहचान अभियोजन साक्षी 3 और 8 ने क्रमशः हमलावरों में से एक के रूप में की थी। अभियोजन साक्षी 5 ने आरोपी सं. 6 की पहचान हमलावरों में से एक के रूप में की थी, और अभियोजन साक्षी 20 ने उसे गैरकानूनी भीड़ के सदस्यों में से एक के रूप में पहचाना था।

i. इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-5 ने गवाही दी थी कि आरोपी सं. 8 ने उस पर लाठी से हमला किया था। अभियोजन साक्षी-20 ने भी उसकी पहचान गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों में से एक के रूप में की थी। अभियोजन साक्षी-3 और 20 ने क्रमशः गवाही दी कि आरोपी सं. 10 ने अभियोजन साक्षी-3 के बाएँ पैर पर गंडासे से और अभियोजन साक्षी-20 ने उसके सिर पर कुदाल से हमला किया। अभियोजन साक्षी-3 और 20 ने क्रमशः गवाही दी कि आरोपी सं. 12 उन हमलावरों में से एक था जिसने उन पर लाठी से हमला किया था। अभियोजन साक्षी-8 ने आरोपी सं. 12 को अपने मृत पति सरजुग महतो पर हमला करते हुए भी देखा था। अभियोजन साक्षी-6 ने गवाही दी कि आरोपी सं. 7 और 13 ने उस पर हमला किया था। श्री मिश्रा ने यह भी दलील दी कि गवाहों को लगी चोटें उनकी गवाही में दिए गए हमले के विवरण के अनुरूप हैं।

ii. श्री मिश्रा ने *जॉय देवराज बनाम केरल राज्य (2024) 8 एससीसी 102* में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए दलील दी कि गवाहों की गवाही में विसंगतियों को उस अराजक घटना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जहाँ कई आरोपियों पर विभिन्न हथियारों से गवाहों पर हमला करने का आरोप है। ऐसी परिस्थितियों में, हथियारों के संबंध में मामूली विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं और गवाहों की विश्वसनीयता को कम नहीं करती हैं। जब प्रत्यक्षदर्शी विवरण चिकित्सा

साक्ष्यों से पूरी तरह पुष्ट होता है, तो ये विसंगतियाँ अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हैं।

- iii. उन्होंने आगे कहा कि घटना के पीछे का मकसद महतो समुदाय के गवाहों और महिला गांव के निवासियों के बीच पुरानी दुश्मनी थी। उन्होंने **बिकाऊ पांडे एवं अन्य बनाम बिहार राज्य (2003) 12 एससीसी 616** मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत समान उद्देश्य का अनुमान गैरकानूनी सभा के सदस्यों के आचरण, भाषा और कृत्यों से लगाया जा सकता है। सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति का भी काफी महत्व है। सभा का समान उद्देश्य सभा के गठन, इस्तेमाल किए गए हथियारों और घटना से पहले, उसके दौरान और बाद में सदस्यों के आचरण से पता लगाया जा सकता है।
- iv. उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, श्री मिश्रा ने दलील दी कि घायल गवाहों, अर्थात् क्रमशः आरोपी सं. 3, 5, 6 और 20, ने प्रत्येक अपीलकर्ता पर विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया है। गैरकानूनी जमावड़ा आग्नेयास्त्रों, कुदाल, सूली, गंडासा, लाठी आदि जैसे घातक हथियारों से लैस था, जो एक ही उद्देश्य को दर्शाता है।
- v. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत आरोपियों के दायित्व के बारे में विस्तार से बताते हुए, श्री सिंह ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत दायित्व, सभा के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तिगत इरादे पर निर्भर नहीं है। उन्होंने **वसंत उर्फ गिरीश अकबरसाब सनावाले बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसकी प्रतिवेदन **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 337** में दी गई है, और कहा कि किसी व्यक्ति को सभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही वह अपराध उनके व्यक्तिगत इरादे के विपरीत हो, बशर्ते कि वह कृत्य समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया हो और वह व्यक्ति उस समय सभा का हिस्सा बना रहा हो। यह प्रावधान एक साझा उद्देश्य के लिए सामूहिक कार्रवाई पर केंद्रित है।
- vi. उन्होंने **मिजाजी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में इस न्यायालय के

निर्णय का भी हवाला दिया, जो 1958 एससीसी ऑनलाइन एससी 95 में दर्ज था, तथा कहा कि जहां कुछ लोग हथियारबंद होकर भूमि पर जबरन कब्जा करने जाते हैं, वहां यह तर्कसंगत रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें पता था कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के दौरान हत्या की संभावना है।

- vii. वर्तमान मामले में अपीलकर्ता घातक हथियारों से लैस थे। इसके अलावा, गवाहों की मौखिक गवाही से यह साबित होता है कि घटनास्थल पर भीड़ के रूप में उनकी उपस्थिति थी। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को पता था कि ज़मीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में जमा हुए लोगों की वजह से मौत हो सकती है।

V. विश्लेषण

42. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात्, हमारे विचारणीय एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है।
43. हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि 24 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिनमें से 5 को फरार आरोपी घोषित किया गया था। मुकदमे के समापन पर, 21 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। जबकि, 3 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। 21 दोषियों में से 19 ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 12 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और 7 को बरी कर दिया। इसलिए, जिन 12 दोषियों की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी, वे इस न्यायालय के समक्ष अपील में आए। हालाँकि, जहाँ तक दो अपीलकर्ताओं (आपराधिक अपील सं. 1187/2014 में मोहम्मद मुस्लिम और आपराधिक अपील सं. 1329/2014 में कैमुद्दीन) का संबंध है, इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार अपीलें रद्द कर दी गईं। तदनुसार, वर्तमान दो अपीलें 10 दोषियों से संबंधित हैं। नीचे दी गई तालिका तस्वीर को और स्पष्ट करेगी:-

वि. न्या. के समक्ष		स्थिति
ए-1	कैमुद्दीन	निधन हो चुका है
ए-2	मो. मुस्लिम	निधन हो चुका है

ए-3	हबीब	
ए-4	आज़म	उच्च न्यायालय द्वारा बरी
ए-5	असरुल	उच्च न्यायालय द्वारा बरी
ए-6	सत्तार	अपीलकर्ता सं. 1 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-7	उदुआ	अपीलकर्ता सं. 2 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-8	रज़ाक्र	अपीलकर्ता सं. 3 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-9	मोह. मशीयत	अपीलकर्ता सं. 4 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-10	अलाउद्दीन उर्फ अल्लू	अपीलकर्ता सं. 5 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-11	होदा	अपीलकर्ता सं. 6 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-12	सलाहुद्दीन उर्फ सल्लू	अपीलकर्ता सं. 7 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-13	मो. मोजिब उर्फ मुजिया	अपीलकर्ता सं. 8 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-14	मो. मिस्टर	अपीलकर्ता सं. 9 आपराधिक अपील सं. 1188/2014 में
ए-15	असलम	वि. न्या. द्वारा बरी
ए-16	आफताब आलम	उच्च न्यायालय द्वारा बरी
ए-17	ज़ैनुल	अपीलकर्ता सं. 1 आपराधिक अपील सं. 1187/2014 में
ए-18	सहाबुद्दीन उर्फ समद्दीन	उच्च न्यायालय द्वारा बरी

ए-19	गरीबुल	
ए-20	मो. खज़ा	उच्च न्यायालय द्वारा बरी
ए-21	बारिक	उच्च न्यायालय द्वारा बरी
ए-22	मो. सिकंदर	उच्च न्यायालय द्वारा बरी
ए-23	कलीमुद्दीन	वि. न्या. द्वारा बरी
ए-24	अलाउद्दीन	वि. न्या. द्वारा बरी

44. इसमें कोई दो राय नहीं कि साक्ष्यों का मूल्यांकन मुख्यतः विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, अगर विचारण न्यायालयों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करके न्याय की विफलता का कारण बना, तो यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करने और मामले की बारीकी से जाँच करने के लिए बाध्य है।

ए. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की व्याख्या

45. यद्यपि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के मूल तत्व बार-बार दोहराए गए हैं और दृढ़तापूर्वक स्थापित हैं, फिर भी सुविधा के लिए उन्हें यहां दोहराया जा रहा है:

- i. पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह होना चाहिए;
- ii. उस गैरकानूनी समूह के किसी भी सदस्य द्वारा कोई अपराध किया जाना चाहिए;
- iii. किया गया अपराध उस समूह के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए, या
- iv. समूह के सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशेष अपराध किए जाने की संभावना है।

46. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में प्रावधान है कि यदि किसी गैरकानूनी जमावड़े (5 या अधिक व्यक्तियों का) के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के साझा उद्देश्य (जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित है) के लिए कोई अपराध किया जाता है, या यदि जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उक्त अपराध उक्त साझा उद्देश्य के लिए किए जाने की संभावना है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करते समय उस जमावड़े का सदस्य था, उस अपराध का दोषी होगा।
47. इस प्रावधान का पहला भाग किसी गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए अपराध की परिकल्पना करता है। जबकि, इस प्रावधान का दूसरा भाग गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए गए अपराध की संभावना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
48. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दो अंगों के बीच अंतर को **मिजाजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के फैसले में स्पष्ट किया गया था, जिसे 1958 एससीसी ऑनलाइन एससी 95 में दर्ज किया गया था। प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं: -

“6. यह धारा भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में व्याख्या का विषय रही है, लेकिन प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य उद्देश्य के संबंध में विधिविरुद्ध समूह के सदस्यों की बैठक के अर्थ में कोई पूर्व-सहमति हो; यदि इसे सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जाए और सभी इसमें सहभागी हों, तो यह पर्याप्त है। मामले को प्रथम भाग के अंतर्गत लाने के लिए, किया गया अपराध उस गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होना चाहिए जिसके आरोपी सदस्य थे। भले ही किया गया अपराध जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के प्रत्यक्ष अभियोजन में न आता हो, फिर भी यह धारा 149 के अंतर्गत आ सकता है यदि यह माना जा सके कि अपराध ऐसा था जिसके बारे में सदस्यों को पता था कि उसका किया जाना संभावित है। 'जानना' का अर्थ केवल संभावना नहीं है, जैसे कि हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के

लिए, यह सर्वविदित है कि जब किसी गाँव में भारी हथियारों से लैस पुरुषों का एक समूह किसी महिला को जबरन ले जाने के लिए निकलता है, तो किसी की हत्या होने की संभावना होती है और गैरकानूनी जमावड़ा के सभी सदस्यों को इस संभावना के बारे में पता होना चाहिए और वे धारा 149 के दूसरे भाग के तहत दोषी होंगे। इसी प्रकार, यदि व्यक्तियों का एक समूह भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए सशस्त्र जाता है, तो यह कहना भी उतना ही सही होगा कि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि हत्या होने की संभावना है, यदि ले जाए जा रहे हथियारों और गैरकानूनी भीड़ के सदस्यों के अन्य आचरण से स्पष्ट रूप से उन सभी की ओर से इस तरह के ज्ञान की ओर इशारा होता है। सबिद अली मामले [(1873) 20 डब्ल्यूआर 5 सीआर] में काउच, सी.जे. की राय के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है कि जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जाता है, तो यह आम तौर पर एक ऐसा अपराध होगा जिसके बारे में गैरकानूनी सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है। हालाँकि, यह विपरीत प्रस्ताव को सत्य नहीं बनाता है; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पहले भाग के अंतर्गत नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दो भागों के बीच के अंतर को अनदेखा या मिटाया नहीं जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने का मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध धारा 149 के पहले भाग के अंतर्गत आता है जैसा कि ऊपर बताया गया है या यह एक ऐसा अपराध था जिसके बारे में सभा के सदस्यों को पता था कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है और यह दूसरे भाग के अंतर्गत आता है।

(जोर दिया गया)

49. "सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि किया गया अपराध सीधे तौर पर सभा के सामान्य उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए, या साक्ष्य के मूल्यांकन पर, ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि कार्य उस सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया हो। **चरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2004) 4 एससीसी 205** में दर्ज मामले में, इस न्यायालय ने माना कि किसी गैरकानूनी सभा के "सामान्य उद्देश्य" के निर्धारण के लिए परीक्षण का मूल्यांकन उसके सदस्यों के आचरण के साथ-साथ आसपास की

परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए। इसका अनुमान सभा की प्रकृति, उसके सदस्यों द्वारा ले जाए गए हथियारों और घटना से पहले, उसके दौरान या बाद में उनके आचरण से लगाया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“13. [...] भारतीय दंड संहिता की धारा 149 रचनात्मक दायित्व पर आधारित है, जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। इसमें समान उद्देश्य पर जोर दिया गया है, समान आशय पर नहीं। किसी गैरकानूनी जमावड़े में केवल उपस्थिति मात्र से कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि कोई समान उद्देश्य न हो और वह उसी समान उद्देश्य से प्रेरित न हुआ हो और वह उद्देश्य धारा 141 में वर्णित उद्देश्यों में से एक न हो। जहाँ किसी गैरकानूनी जमावड़े का समान उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, वहाँ आरोपियों को धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जमावड़े में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 में निर्दिष्ट समान उद्देश्यों में से एक या अधिक को पूरा किया था। विधि के सामान्य प्रस्ताव के रूप में यह प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि जब तक किसी व्यक्ति, जिस पर गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होने का आरोप है, के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह जमावड़ा का सदस्य है। केवल एक ही बात आवश्यक है कि उसे यह समझना चाहिए था कि सभा गैरकानूनी थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को अंजाम दे सकती थी। “उद्देश्य” शब्द का अर्थ उद्देश्य या योजना है और इसे “सामान्य” बनाने के लिए, इसे सभी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए, जो सभा का गठन करते हैं, अर्थात्, वे सभी इसके बारे में जानते हों और इसमें सहमत हों। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक सामान्य उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर सभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा बनाया जा सकता है और अन्य सदस्य बस इसमें शामिल होकर इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित, परिवर्तित या त्यागा जा सकता है। धारा 149 में प्रकट होने वाले “सामान्य

उद्देश्य के कार्यान्वयन में" अभिव्यक्ति को सख्ती से "सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए" के समतुल्य समझा जाना चाहिए। उद्देश्य की प्रकृति के कारण इसे सामान्य उद्देश्य से तत्काल संबद्ध होना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय होना आवश्यक है और उद्देश्य केवल एक विशेष चरण तक ही विद्यमान रह सकता है, उसके बाद नहीं। एक विधिविरुद्ध समूह के सदस्यों का उद्देश्य एक निश्चित सीमा तक ही समुदाय हो सकता है, जिसके आगे उनके उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है और प्रत्येक सदस्य को अपने सामान्य उद्देश्य के कार्यान्वयन में संभावित रूप से क्या किया जा सकता है, इसकी जानकारी न केवल उसके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भिन्न हो सकती है, बल्कि इस सीमा तक भी भिन्न हो सकती है कि वह उद्देश्य के समुदाय को किस हद तक साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप, एक ही समूह के विभिन्न सदस्यों पर धारा 149 भारतीय दंड संहिता का प्रभाव भिन्न हो सकता है।

14. "साझा उद्देश्य" "साझा इरादे" से अलग है क्योंकि इसके लिए हमले से पहले किसी पूर्व सहमति और विचारों की एक समान बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है कि प्रत्येक का उद्देश्य एक ही हो और उनकी सं. पाँच या अधिक हो और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करें। किसी सभा का "साझा उद्देश्य" उसे बनाने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से, और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना चाहिए। यह सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण के तरीके से पता लगाया जा सकता है। घटना के किसी विशेष चरण में गैरकानूनी सभा का साझा उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से तथ्य का प्रश्न है जिसे सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा धारण किए गए हथियारों, और घटना स्थल पर या उसके आस-पास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सभी मामलों में, एक गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ, उसे कार्रवाई में तब्दील किया जाए या सफल हो। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा जो एकत्रित होने के समय गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सभा को गैरकानूनी बनाने के लिए आवश्यक इरादा या उद्देश्य शुरू में ही अस्तित्व में आ जाए।

गैरकानूनी इरादे के निर्माण का समय महत्वपूर्ण नहीं है। एक सभा जो अपने आरंभ में या उसके बाद कुछ समय के लिए वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह घटनास्थल पर घटना के दौरान विकसित हो सकती है।

(जोर दिया गया)

50. संक्षेप में कहें तो, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 किसी गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्यों को रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाती है, जब उस जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से कोई अपराध किया जाता है या जमावड़े के सदस्यों को पता होता है कि ऐसा अपराध होने की संभावना है। हालाँकि, ऐसा दायित्व केवल इस बात के प्रमाण पर ही लगाया जा सकता है कि कार्य एक सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया था। धारा 149 के मूल तत्वों को संविधान पीठ ने **मोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य** के निर्णय में संक्षेप में समझाया था, जो एआईआर 1963 एससी 174 में दर्ज है। यह इस प्रकार है:-

“8. धारा 149 द्वारा निर्दिष्ट किसी अपराध के आवश्यक तत्वों के संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति संदेह में नहीं है। धारा 149 किसी गैरकानूनी जमावड़े के सभी सदस्यों के लिए प्रतिनिधिक या रचनात्मक आपराधिक दायित्व निर्धारित करती है, जहाँ ऐसी गैरकानूनी जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के लिए या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के लिए ऐसा किया जाना संभावित है। इस प्रकार यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 149 के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि अपराध किसी गैरकानूनी जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा किया गया होगा, और धारा 141 यह स्पष्ट करती है कि केवल तभी गैरकानूनी जमावड़ा बनता है जब पाँच या अधिक व्यक्ति एक जमावड़ा लगाते हैं, बशर्ते कि उस जमावड़े को लगाने वाले व्यक्तियों के सामान्य उद्देश्य के संबंध में उक्त धारा की अन्य आवश्यकताएँ पूरी हों। दूसरे शब्दों में, किसी गैरकानूनी जमावड़े की एक आवश्यक शर्त यह है कि उसके सदस्यों की सं. पाँच या अधिक होनी चाहिए। [...]”

(जोर दिया गया)

51. निस्संदेह, एक बार जब किसी गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों के बीच एक समान उद्देश्य का अस्तित्व स्थापित हो जाता है, तो यह साबित करना अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक सदस्य ने कोई प्रत्यक्ष कार्य किया है। इस प्रावधान के तहत दायित्व तभी लागू होता है जब यह निश्चित हो जाए कि किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी थी कि किया गया अपराध उस समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने का एक संभावित परिणाम था, जिससे वह गैरकानूनी जमावड़े का "सदस्य" बन जाता है।
52. इस तथ्य का पता लगाते समय, यह विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि क्या उस सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति भी शामिल थे जो केवल निष्क्रिय दर्शक थे और सभा के सामान्य उद्देश्य की जानकारी के बिना, केवल जिज्ञासावश सभा में शामिल हुए थे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धारा 149 का मूल "सामान्य उद्देश्य" है।

क. निर्दोष दर्शक बनाम गैरकानूनी सभा का सदस्य

53. एक बार जब धारा 149 की दो व्यापक अनिवार्यताएं पूरी हो जाती हैं, यानी, (1) किसी गैरकानूनी जमावड़े के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, या (2) यदि जमावड़े के सदस्यों को पता था कि उक्त अपराध उक्त सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किए जाने के समय जमावड़े का सदस्य था, उस अपराध का दोषी माना जाएगा।
54. साथ ही, घटनास्थल पर मात्र उपस्थिति किसी व्यक्ति को गैरकानूनी जमावड़े का स्वतः सदस्य नहीं बना देती, जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि ऐसे आरोपी का भी उस जमावड़े में समान उद्देश्य था। मात्र दर्शक, जिसकी कोई विशिष्ट भूमिका न हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दायरे में नहीं आएगा। अभियोजन पक्ष को, यथोचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिस्थितियों के माध्यम से, यह स्थापित करना होगा कि आरोपियों का गैरकानूनी जमावड़े में समान उद्देश्य था। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई व्यक्ति निष्क्रिय दर्शक है या निर्दोष दर्शक, परीक्षण वही है जो किसी समान उद्देश्य के अस्तित्व का पता लगाने के लिए लागू होता है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से एक समान उद्देश्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाना है, जैसे:

क. सभा जिस समय और स्थान पर गठित हुई थी;

- ख. अपराध-स्थल पर अथवा उसके निकट उसके सदस्यों का आचरण एवं व्यवहार;
- ग. सभा का सामूहिक आचरण, जो उसके व्यक्तिगत सदस्यों के आचरण से भिन्न हो;
- घ. अपराध के पीछे निहित उद्देश्य;
- ङ. घटना के घटित होने का तरीका;
- च. साथ रखे गए तथा प्रयुक्त किए गए हथियारों की प्रकृति;
- छ. पहुँचाई गई चोटों की प्रकृति, सीमा एवं संख्या तथा अन्य प्रासंगिक विचारणीय परिस्थितियाँ।

i. गैरकानूनी सभा के सदस्यों को दोषी ठहराने में विवेक का नियम

55. इस न्यायालय ने, सावधानी के तौर पर, निर्दोष दर्शकों या निष्क्रिय दर्शकों को केवल उनकी उपस्थिति के आधार पर दोषी ठहराए जाने से बचाने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। हालाँकि, यह सावधानी संबंधी नियम रचनात्मक दायित्व के सिद्धांत को कमजोर नहीं करता है, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी प्रत्यक्ष कृत्य का प्रमाण अनिवार्य नहीं है। जहाँ बड़ी सं. में व्यक्तियों की उपस्थिति स्थापित हो और कई लोग इसमें शामिल हों, वहाँ विवेकशीलता इस सावधानी के नियम का कड़ाई से पालन करने की माँग करती है।
56. *मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1964* एससीसी ऑनलाइन एससी 30 में प्रकाशित, में 40 व्यक्तियों पर कई अपराध करने का आरोप लगाया गया था, जिनमें से प्रमुख भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 149 के अंतर्गत थे। आरोपियों पर बंदूक, भाले, तलवार, गंडासे और लाठी से लैस होने का आरोप था। मौखिक साक्ष्यों पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिकांश गवाह अभियोजन पक्ष के थे। इसके अलावा, सभी गवाहों के साक्ष्यों ने घटना का विवरण समान रूप से दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक कम से कम चार गवाह आरोपियों के खिलाफ एक समान बयान नहीं देते, तब तक उनके खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं कहा जा सकता। इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा लागू किए गए मानदंड को स्वीकार किया और माना कि बड़ी सं. में अपराधियों और पीड़ितों से जुड़े मामलों में दोषसिद्धि तभी कायम रह सकती है जब दो या तीन या अधिक विश्वसनीय गवाहों के सुसंगत बयानों द्वारा इसका समर्थन किया जाए। प्रासंगिक

अवलोकन नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“16. श्री साहनी ने यह भी आग्रह किया कि अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया परीक्षण यांत्रिक है। उनका तर्क है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, एक गवाह द्वारा दिया गया विश्वसनीय साक्ष्य किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त होगा, जबकि आधा दर्जन गवाहों द्वारा दिया गया साक्ष्य, जो विश्वसनीय नहीं है, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह निस्संदेह सत्य है; लेकिन जहाँ किसी आपराधिक न्यायालय को बड़ी सं. में अपराधियों और बड़ी सं. में पीड़ितों से जुड़े अपराध के कारित होने से संबंधित साक्ष्यों पर विचार करना होता है, वहाँ यह परीक्षण अपनाना सामान्य है कि दोषसिद्धि तभी कायम रह सकती है जब उसे दो या तीन या अधिक गवाहों द्वारा समर्थित किया जाए जो घटना का सुसंगत विवरण दें। एक अर्थ में, इस परीक्षण को यांत्रिक कहा जा सकता है; लेकिन यह समझना कठिन है कि इसे कैसे तर्कहीन या अनुचित माना जा सकता है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि इस परीक्षण को अपनाने के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत की जा सकती है। यदि अभियोजन पक्ष यह कहने का हकदार है कि सात आरोपियों को इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि उनके मामले न्यायालय के तर्कों को संतुष्ट नहीं करते थे। चार गवाहों का यांत्रिक परीक्षण किया गया था, और यदि उक्त परीक्षण लागू नहीं किया गया होता, तो उन्हें दोषी ठहराया जा सकता था। निस्संदेह, साक्ष्य की गुणवत्ता ही मायने रखती है, न कि साक्ष्य देने वाले गवाहों की सं.। लेकिन कभी-कभी ऐसा परीक्षण अपनाना उपयोगी होता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अपनाया है।”

(जोर दिया गया)

57. **मुथु नायकर बनाम तमिलनाडु राज्य, (1978) 4 एससीसी 385** में दर्ज मामले में, एक गाँव में दो गुटों के बीच पाइपलाइन बिछाने को लेकर विवाद हुआ था। मामले के तथ्यों के अनुसार, 28 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और 34 गवाहों से पूछताछ की गई, जिनमें से 6 घायल प्रत्यक्षदर्शी थे। न्यायालय ने कहा कि जब भी ग्रामीण समाज में गुटों के बीच लड़ाई होती है, तो कई लोग उत्सुक दर्शकों के रूप में घटनास्थल पर उपस्थित होते हैं। ऐसे मामले में, केवल सभा में उपस्थिति को इस बात का प्रमाण नहीं

माना जाएगा कि वह व्यक्ति गैरकानूनी सभा का सदस्य था। न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपियों की उपस्थिति को संतोषजनक रूप से सिद्ध माना जाएगा यदि उनके खिलाफ कम से कम तीन गवाहों का विश्वसनीय साक्ष्य हो। संबंधित अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:-

“6. जहाँ हाथापाई हो रही हो और बड़ी सं. में हमलावर और गवाह अलग-अलग जगहों से और घटना के अलग-अलग चरणों में घटना के गवाह होने का दावा कर रहे हों और जहाँ इस मामले में सबूत निस्संदेह पक्षपातपूर्ण हों, वहाँ निर्दोष को झूठे दोषियों के साथ शामिल किए जाने की स्पष्ट संभावना से आसानी से इनकार नहीं किया जा सकता। गुटबाजी से ग्रस्त समाज में, जहाँ कोई घटना प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच घटित होती है, यह अपरिहार्य है कि सबूत पक्षपातपूर्ण प्रकृति के होंगे। ऐसी स्थिति में, केवल पक्षपातपूर्ण होने के आधार पर पूरे सबूत को खारिज करना हमारे देश के ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं से आँखें मूंद लेने के समान है। अगर ऐसा आसान रास्ता अपनाया गया तो बड़ी सं. में आरोपी बिना सजा के बच जाएँगे। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे सामने जो मामला सामने आया है, उसमें विरोधी गुट के अधिक से अधिक लोगों को केवल नाम लेकर, जैसे कि वे हाथापाई में देखे गए थे, शामिल करने की आसान प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अक्सर स्पष्ट होती है और जिससे बचना चाहिए, इसलिए, साक्ष्य की अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए। ऐसी ही स्थिति में, इस न्यायालय ने मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1965 एससी 202 : (1964) 8 एससीआर 133 : (1965) 1 क्रि. एलजे 226] में प्रत्येक आरोपी की भूमिका के बारे में आश्वस्त होने के लिए एक व्यावहारिक परीक्षण अपनाने का रास्ता अपनाया। कुछ हद तक यह अपरिहार्य है कि हम इसे अपनाएँ।

7. साक्ष्यों की जांच करने से पहले यह स्पष्ट कर देना भी आवश्यक है कि जब भी किसी घटनाहीन ग्रामीण समाज में कुछ असामान्य घटित होता है, खासकर जब स्थानीय समुदाय गुटबाजी में घिरा हो और गुटों के बीच लड़ाई हो जाती है, तो काफी सं. में लोग घटना स्थल पर घटना में भाग लेने के लिए नहीं बल्कि उत्सुक दर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसी घटना में केवल गैरकानूनी सभा में उपस्थिति को इस निष्कर्ष पर ले जाने वाला नहीं माना जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में गैरकानूनी सभा में मौजूद था। गैरकानूनी सभा के प्रत्येक

सदस्य पर प्रतिनिधिक दायित्व लागू होगा यदि गैरकानूनी सभा का वह सदस्य या तो प्रत्यक्ष कृत्य द्वारा अपराध करने में भाग लेता है या जानता है कि जो अपराध किया गया है वह गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा किया जाने की संभावना थी और वह गैरकानूनी सभा का सदस्य बन जाता है या बना रहता है। यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी सभा का सदस्य बन जाता है और गैरकानूनी सभा में उसका शामिल होना स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है, तो अपराध के प्रत्यक्ष कृत्य में उसकी भागीदारी साबित करने की आवश्यकता नहीं है यदि यह दिखाया जा सके कि वह जानता था कि ऐसा अपराध गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह पता लगाते समय कि कोई व्यक्ति एक जिज्ञासु दर्शक था या गैरकानूनी सभा का सदस्य, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गाँव में जीवन आमतौर पर मामूली झगड़ों को छोड़कर घटनाहीन होता है जहाँ गाँव का समुदाय गुटबाजी में बंटा होता है और जब कोई गंभीर अपराध होता है तो लोग बस यह जानने के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि क्या हो रहा है। इस मामले में हमारे पास यह बताने का अवसर होगा कि ऐसे आरोपी हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराया गया है, लेकिन जिनके संबंध में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि वे केवल दर्शक थे और उन्हें शायद ही गैरकानूनी सभा का सदस्य कहा जा सकता है

XXX

39. अब, बाकी आरोपियों के मामले की ओर मुड़ते हुए, हम सामान्यतः उन आरोपियों की उपस्थिति को संतोषजनक रूप से सिद्ध मान लेंगे जिनके संबंध में कम से कम तीन गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं और साक्ष्यों का विश्लेषण करते समय, हम अभियोजन साक्षी 19 के साक्ष्य को स्वीकार करने में काफ़ी धीमे होंगे, जो, जैसा कि हम अभी इंगित करेंगे, धारा 161, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उसके बयान से भौतिक रूप से विरोधाभासी है। इस दृष्टिकोण से मामले को देखते हुए, हम संक्षेप में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अभियोजन साक्षी 1, 19, 20 और 24 द्वारा आरोपी 6 की उपस्थिति का लगातार उल्लेख किया गया है और यह साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करता है कि आरोपी 6 गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य था और उस पर धारा 148 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाया गया है।

XXX

54. अब शीर्ष 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 और 30 के अंतर्गत आरोपों की ओर आते हुए, यह इंगित करना आवश्यक है कि इन आरोपों के अंतर्गत सभी अभियुक्तों को प्रत्येक व्यक्तिगत अभियुक्त द्वारा किसी-न-किसी अभियोजन साक्षी के विरुद्ध किए गए विशिष्ट अपराधों के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया गया था। बिना विस्तार में जाए हम तत्काल यह कहना आवश्यक समझते हैं कि इस प्रकृति के मामले में, जहाँ एक बड़ी भीड़ एकत्रित होती है और जिनमें से सभी व्यक्तियों के अवैध जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को साझा करने का प्रमाण नहीं है, किसी एक अभियुक्त द्वारा किसी विशेष साक्षी पर किया गया एकाकी आक्रमण, अवैध जमावड़े के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किया गया आक्रमण नहीं कहा जा सकता, ताकि शेष अभियुक्तों पर यह ज्ञान आरोपित किया जा सके कि ऐसा अपराध अवैध जमावड़े के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में किए जाने की संभावना थी। उदाहरणार्थ, यदि यह आरोप हो कि किसी अभियुक्त ने पत्थर फेंककर उस व्यक्ति को चोट पहुँचाई जो उस पत्थर की दिशा में आ गया, तो क्या यह कहा जा सकता है कि अवैध जमावड़े के अन्य सभी सदस्यों को यह ज्ञात था कि ऐसा अपराध किया जाएगा? अतः, हम शीर्ष 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 और 30 के अंतर्गत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार उक्त आरोपों के अंतर्गत अभियुक्तों की दोषसिद्धि तथा उनके लिए निर्धारित दण्डादेश निरस्त किए जाते हैं और वे इन आरोपों से दोषमुक्त किए जाते हैं।

(जोर दिया गया)

58. जहाँ बड़ी सं. में व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, न्यायालयों को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, विशेष रूप से, यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अस्पष्ट हैं। **शेरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** में, 1991 पूरक (2) एससीसी 437 में दर्ज, छह प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के बारे में गवाही दी थी, और शिकायतकर्ता ने नौ आरोपियों पर प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया था। एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपनी गवाही में मृतक पर हमला करने वाले पांच और आरोपियों के नाम बताए। अन्य के बारे में, उसने उल्लेख किया था कि आरोपी व्यक्ति लाठियों से लैस थे; किसी पर कोई प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि गवाहों के साक्ष्य की उनके पूर्व बयानों के आधार पर बारीकी से जांच की जानी चाहिए। इस न्यायालय ने केवल उन्हीं लोगों को दोषी ठहराना उचित समझा, जिनका नाम

प्रारंभिक प्रतिवेदन के चरण से लगातार लिया गया था। संबंधित अंश इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“4. हमने साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी चश्मदीद गवाह मौजूद थे। उनकी प्रतिपरीक्षण में कोई महत्वपूर्ण बात सामने नहीं आई। हालाँकि, चश्मदीद गवाहों ने केवल इन अपीलकर्ताओं के नाम लिए और उनकी पहचान की। इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या सभी अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना सुरक्षित है। इस प्रकार के मामले में, गवाहों के साक्ष्य की उनके पूर्व बयानों के आलोक में गहन जाँच की जानी चाहिए। सबसे प्रारंभिक प्रतिवेदन अर्थात् प्राथमिकी की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने वर्तमान बयान में उन्होंने संबंधित आरोपियों द्वारा रखे गए हथियारों का वर्णन किया है, लेकिन हमें सबसे प्रारंभिक प्रतिवेदन में दिए गए संस्करण को देखना होगा। उस प्रतिवेदन में अभियोजन साक्षी 1 ने पिछली कार्यवाही का उल्लेख करने के बाद वर्तमान घटना का काफी विस्तृत विवरण दिया है। उसने गवाहों के नाम और तीन मृत व्यक्तियों के नाम भी बताए हैं। फिर उसने आरोपियों के नामों की एक लंबी सूची दी और आम तौर पर यह कहा गया है कि वे सभी उकसा रहे थे और अभियोजन साक्षी और अन्य हिंदुओं को घेर लिया और उन पर हमला किया। लेकिन कुछ हद तक अपीलकर्ता 1, 4, 5, 7, 8, 10, 17, 22 और 25 पर विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि ये नौ आरोपी घातक हथियारों से लैस थे और मृतक राम नारायण और अन्य पर हमला करते देखे गए थे। अब वर्तमान बयान में उन्होंने अपने बयान में सुधार किया है और कहा है कि इन नौ आरोपियों के अलावा, पाँच और व्यक्तियों ने भी मृतक और अन्य पर हमला किया था। इस भिन्नता को देखते हुए, हमारा मानना है कि केवल उन्हीं अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना सुरक्षित है जिनका उल्लेख प्रारंभिक प्रतिवेदन के चरण से ही हमले में भाग लेने के रूप में लगातार किया गया है। बाकी के संबंध में, अभियोजन साक्षी 1 ने व्यापक रूप से उल्लेख किया है कि वे लाठियों से लैस थे। उन्होंने उनमें से किसी पर भी किसी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य किसी भी लाठियों के इस्तेमाल की बात को खारिज करते हैं। डॉक्टर ने पाया कि शवों और घायल अभियोजन साक्षी पर केवल गंभीर चोटें थीं। इसलिए,

अभियोजन पक्ष के इस मामले को स्वीकार करना कठिन है कि अन्य अपीलकर्ता उन अपराधों को करने के उद्देश्य से गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिनका उन पर आरोप लगाया गया है। हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 लागू करना और उनमें से प्रत्येक को रचनात्मक रूप से उत्तरदायी ठहराना बेहद असुरक्षित है। लेकिन जहाँ तक उपरोक्त नौ आरोपियों का संबंध है, अभियोजन पक्ष का कथन एकरूप है, अर्थात् वे तलवारों और कुल्हाड़ियों जैसे घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने मृतक और अन्य लोगों पर हमला किया। उनके विरुद्ध यह मजबूत परिस्थिति उनकी उपस्थिति और साथ ही गैरकानूनी सभा की उनकी सदस्यता को भी स्थापित करती है।[...]”

(जोर दिया गया)

59. **अकबर शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2009) 7 एससीसी 415** में दर्ज मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जटिल तथ्यों के मामलों में विवेक का नियम लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि गवाह के कठघरे में आरोपी के रूप में उनका उल्लेख किए जाने से कहीं अधिक कुछ आवश्यक होगा। न्यायालय के समक्ष यह राय बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि आरोपियों का उद्देश्य एक ही था। प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

“41. इस प्रकार के मामले में विवेक का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का नाम गवाहों द्वारा अभियुक्त के रूप में लिया गया है, पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय के समक्ष ऐसा अतिरिक्त सामग्री होना आवश्यक है, जिससे यह राय बनाई जा सके कि उन्होंने एक सामान्य उद्देश्य साझा किया था। यह न तो अस्वीकार किया गया है और न ही विवादित है कि जहाँ पाँच भाइयों को अभियुक्त बनाया गया, वहाँ एक भाई ने अभियोजन साक्ष्य-9 के विरुद्ध बयान दिया था और पुत्रों को भी इसलिए अभियुक्त बनाया गया क्योंकि उनके पिता ने उनके विरुद्ध बयान दिया था। जबकि अभियोजन साक्ष्य-1 ने अपने बयान में यह अस्वीकार किया कि अभियुक्त ने उस मामले में बयान दिया था, जिसमें एक पुत्र को डोल गोविन्द आचार्य (पूर्व प्रधान) की हत्या का दोषी पाया गया था, अभियोजन साक्ष्य-9 ने स्वीकार किया कि उक्त हत्या दिन-दहाड़े की गई थी। झूठे फँसाए जाने के अन्य कारण भी हो सकते थे, इस संभावना से भी इंकार नहीं

किया जा सकता।

XXX

43. हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि अकबर और कंकू का नाम दोनों गवाहों ने लिया है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं बताया गया है। इसलिए, हमारा मानना है कि उनकी उपस्थिति और/या साझा उद्देश्य के संबंध में संदेह जायज़ तौर पर उठता है। ऐसा कहते हुए, हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि घटना आधी रात को हुई थी। गाँव में दो समूहों के बीच दुश्मनी स्वीकार की जाती है। लेकिन, हम इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति को आजीवन कठोर कारावास नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही वह केवल एक दर्शक रहा हो और उसके अलावा और कुछ नहीं था।”

(जोर दिया गया)

60. **सुबल घोराई** (उपरोक्त) मामले में, हथियारों से लैस लगभग 200/250 लोगों ने हमला किया था, जिसमें तीन लोग घायल हो गए थे। विचारण न्यायालय ने 36 लोगों को दोषी ठहराया था। न्यायालय ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में निहित रचनात्मक दायित्व को केवल सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए गए कार्यों तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा एक स्पष्ट कार्य का होना यह साबित करेगा कि उसने सामान्य उद्देश्य को साझा किया था। यह साबित किया जाना चाहिए कि आरोपी न केवल गैरकानूनी सभा का सदस्य था, बल्कि सभी चरणों में सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करता था जब वह सभा का हिस्सा था। साथ ही, न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायालयों को केवल निष्क्रिय दर्शकों को दोषी ठहराने की संभावना से सावधान रहना चाहिए। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं: -

“52. उपरोक्त निर्णय धारा 149 भारतीय दंड संहिता के दायरे को रेखांकित करते हैं। हमें सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान मामले की उनके प्रकाश में जांच की जा सके। धारा 141 भारतीय दंड संहिता गैरकानूनी जमावड़े को पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े के रूप में परिभाषित करती है। अपराध करने के लिए उनका सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। धारा 142 भारतीय दंड संहिता यह मानती है कि जो कोई भी ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी जमावड़े को गैरकानूनी बनाते हैं, जानबूझकर उसमें शामिल होता है वह उसका सदस्य होगा। धारा

143 भारतीय दंड संहिता गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य होने के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 149 भारतीय दंड संहिता गैरकानूनी जमावड़े के प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक दायित्व का प्रावधान करती है यदि उस जमावड़े के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में उसके किसी सदस्य द्वारा या उस जमावड़े के ऐसे सदस्यों द्वारा, जो उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना जानते थे, कोई अपराध किया जाता है। गैरकानूनी जमावड़े का सबसे महत्वपूर्ण घटक सामान्य उद्देश्य है। उस सभा में शामिल व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य उस धारा के खंड "प्रथम", "द्वितीय", "तृतीय", "चतुर्थ" और "पाँचवें" में वर्णित कोई कार्य या कार्य करना है। सामान्य उद्देश्य क्षणिक आवेग में बनाया जा सकता है। आम सभा के सदस्यों द्वारा अपनाया गया आचरण एक प्रासंगिक कारक है। गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य किस समय बना, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक बार जब व्यक्ति का मामला धारा 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आता है, तो यह प्रश्न कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, महत्वहीन हो जाएगा। यदि गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के लिए कोई अपराध किया जाता है, तो गैरकानूनी सभा का कोई भी सदस्य जो अपराध के समय उपस्थित था और जिसने उस सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था, उस अपराध के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही उसके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य न किया गया हो। यदि हथियारों से लैस व्यक्तियों की एक बड़ी भीड़ लक्षित पीड़ितों पर हमला करती है, तो सभी वास्तविक हमले में भाग नहीं ले सकते हैं। यदि कुछ सदस्यों द्वारा ले जाए गए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो यह उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से अपराध के लिए उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा यदि वे गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करते थे।

53. लेकिन रचनात्मक दायित्व की इस अवधारणा को इतना नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि निर्दोष दर्शकों को गलत तरीके से फंसाया जा सके। अक्सर, लोग जिज्ञासावश अपराध स्थल पर इकट्ठा होते हैं। वे गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं करते हैं। यदि बड़ी सं. में लोगों के खिलाफ एक सामान्य आरोप लगाया जाता है, तो न्यायालय को सतर्क रहना होगा। उसे केवल निष्क्रिय दर्शकों को दोषी ठहराने की संभावना से बचना चाहिए, जिनका गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं था। जब तक उचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिस्थितियाँ

अभियोजन पक्ष के मामले को यह आश्वासन नहीं देती कि उन्होंने गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया था, उन्हें धारा 149 भारतीय दंड संहिता की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह साबित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न केवल किसी चरण में, बल्कि सभी महत्वपूर्ण चरणों में गैरकानूनी सभा का सदस्य था और सभी चरणों में सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करता था। न्यायालय के पास यह राय बनाने के लिए कुछ सामग्री होनी चाहिए कि आरोपियों का उद्देश्य समान था। किसी विशेष चरण में गैरकानूनी जमावड़े का उद्देश्य क्या है, यह निर्धारित करने के लिए हमले से पहले और हमले के समय गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों के आचरण, अपराध स्थल पर या उसके आस-पास उनके व्यवहार, अपराध का उद्देश्य, उनके द्वारा ले जाए गए हथियार और ऐसे अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। अपराधिक न्यायालय को अपराध में निर्दोष लोगों को शामिल होने से बचाने के लिए साक्ष्यों का आकलन करने का यह कठिन और सावधानीपूर्वक अभ्यास करना होगा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित ये सिद्धांत रचनात्मक दायित्व की अवधारणा को कमजोर नहीं करते हैं। इनमें सावधानी का नियम निहित है।

(जोर दिया गया)

61. इस मुद्दे पर कानून का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि जहाँ बड़ी सं. में व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोप हों, वहाँ न्यायालय को अस्पष्ट या सामान्य साक्ष्य के आधार पर सभी को दोषी ठहराने से पहले अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए, न्यायालयों को कुछ ठोस और विश्वसनीय सामग्री की तलाश करनी चाहिए जो आश्वासन दे। केवल उन्हीं लोगों को दोषी ठहराना सुरक्षित है जिनकी उपस्थिति न केवल प्राथमिकी के चरण से ही लगातार स्थापित हो, बल्कि जिनके विरुद्ध ऐसे प्रत्यक्ष कार्य भी किए गए हों जो गैरकानूनी जमावड़े के सामान्य उद्देश्य को बढ़ावा देते हों।

ख. गवाहों के साक्ष्य की सराहना से संबंधित कानून के सिद्धांत

62. इस न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह** मामले में, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 390 में दर्ज, जिसमें हम में से एक, जे.बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ति, पीठ का हिस्सा थे, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करने के लिए दो प्रमुख बातों पर जोर दिया था। यह इस प्रकार था:-

“57. सरल शब्दों में कहें तो, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करते समय, दो मुख्य विचारणीय बिंदु होते हैं: क्या मामले की परिस्थितियों में, घटनास्थल पर या ऐसी परिस्थितियों में उनकी उपस्थिति पर विश्वास करना संभव है जो उनके द्वारा बताए गए तथ्यों को उनके द्वारा प्रमाणित करना संभव बनाती हैं, और दूसरा, क्या उनके साक्ष्य में कुछ भी स्वाभाविक रूप से असंभव या अविश्वसनीय है। इन दोनों विचारों के संबंध में, उन गवाहों से प्राप्त या अन्य साक्ष्यों द्वारा स्थापित परिस्थितियाँ, जो उनकी उपस्थिति को असंभव बनाती हैं या उनके बयानों की सत्यता को बदनाम करती हैं, उस मूल्य को प्रभावित करेंगी जो न्यायालय उनके साक्ष्य को प्रदान करेगा। यद्यपि ऐसे मामलों में जहां आरोपी की दलील महज शिक्षा का एक स्पष्ट दावा है, फिर भी अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य की जांच उसके अपने गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए, जहां आरोपी एक निश्चित दलील पेश करता है या एक सकारात्मक मामला पेश करता है जो अभियोजन पक्ष के साथ असंगत है, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के मूल्य का आकलन करते समय ऐसी दलील या मामले की प्रकृति और इसके संबंध में संभावनाओं को भी ध्यान में रखना होगा।

(जोर दिया गया)

63. इस स्तर पर, हम घायल प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही के मूल्यांकन पर कानून के स्थापित सिद्धांतों पर भी चर्चा करना चाहेंगे। घायल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को कानून में विशेष दर्जा दिया गया है क्योंकि उस व्यक्ति पर लगी चोटें इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि गवाह घटनास्थल पर मौजूद था। न्यायालयें घायल प्रत्यक्षदर्शी की गवाही को यह मानकर विश्वसनीय मानती हैं कि गवाह अपने वास्तविक हमलावर को बिना सजा के नहीं छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार, जब तक कि किसी प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए ठोस आधार न हों बड़े विरोधाभासों और विसंगतियों के कारण, आमतौर पर ऐसे साक्ष्य पर भरोसा किया जाना चाहिए।

64. **बालू सुदाम खालदे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2023) 13 एससीसी 365** में दर्ज मामले में, हममें से एक, जे.बी. पारदीवाला, जे. को इस विषय पर कानून की व्याख्या करने का लाभ मिला:-

“26. जब किसी घायल प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना हो, तो न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखना

आवश्यक है:

26.1. घटना के समय और स्थान पर घायल प्रत्यक्षदर्शी की उपस्थिति पर तब तक संदेह नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके बयान में भौतिक विरोधाभास न हों।

26.2. जब तक साक्ष्य द्वारा अन्यथा स्थापित न हो जाए, यह विश्वास किया जाना चाहिए कि एक घायल गवाह वास्तविक अपराधियों को भागने नहीं देगा और आरोपियों को झूठा फंसाएगा।

26.3. घायल गवाह के साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य अधिक होता है और जब तक बाध्यकारी कारण न हों, उनके बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

26.4. प्राकृतिक आचरण में कुछ अलंकरण या मामूली विरोधाभासों के कारण घायल गवाह के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता।

26.5. यदि किसी घायल गवाह के साक्ष्य में कोई अतिशयोक्ति या अप्रासंगिक अलंकरण हो, तो ऐसे विरोधाभास, अतिशयोक्ति या अलंकरण को घायल के साक्ष्य से हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन संपूर्ण साक्ष्य को नहीं।

26.6. अभियोजन पक्ष के संस्करण के व्यापक आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए और विसंगतियों को, जो आमतौर पर समय बीतने के साथ स्मृति हानि के कारण आती हैं, हटा दिया जाना चाहिए।”

65. उपरोक्त विधि सिद्धांतों और सावधानी के नियम को ध्यान में रखते हुए, अब हम अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन और चर्चा करेंगे। यह मामला पाँच घायल प्रत्यक्षदर्शियों और घटना के दो प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्यों के इर्द-गिर्द घूमता है। साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जाँच करने पर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौखिक गवाही में भौतिक विसंगतियाँ और अलंकरण हैं जो मामले की जड़ तक पहुँचते हैं।

66. घायल प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी-20, जिसके पुलिस बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, के मौखिक साक्ष्य से संकेत मिलता है कि जमीन के बंदोबस्त को लेकर उसका आरोपियों से कोई विवाद नहीं था। इसके अलावा, उसने पुलिस के सामने यह कहने से

इनकार किया कि आरोपी इसलिए छिपे हुए थे क्योंकि वे धान की कटाई का विरोध कर रहे थे। वह धान काटने वाले व्यक्तियों की पहचान नहीं कर सका और बल्कि उन्हें मजदूर बताया। फर्दबयान में उसने कहा कि घटना से एक दिन पहले उसने सरकार द्वारा उसे आवंटित खेत से धान काटा था और इस कारण से, आरोपी सं. 2, 16, 17 और 21 क्रमशः 400 से 500 अन्य व्यक्तियों के साथ हथियारों के साथ छिपे हुए थे ताकि उसे धान की आगे कटाई करने से रोका जा सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने स्वीकार किया कि वह हमलावरों के नाम नहीं बता सका जैसा कि अभियोजन साक्षी 3, 6 और 10 ने बताया था हालाँकि, फर्दबयान में, 41 हमलावरों का नाम लेते हुए, अभियोजन साक्षी-20 ने कहा कि क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 5, 6 और 10 ने उसे हमलावरों के बारे में बताया था।

67. अभियोजन साक्षी-20 का बयान उसके फर्दबयान से बिल्कुल अलग है। अपनी मौखिक गवाही में, अभियोजन साक्षी-20 ने स्वीकार किया कि हमले के बाद वह बेहोश हो गया था और इसलिए, उन हमलावरों के नाम नहीं बता सका जिन्होंने क्रमशः अभियोजन साक्षी 3, 6 और 10 पर हमला किया था। इसके ठीक विपरीत, उसके फर्दबयान में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि अभियोजन साक्षी 3, 5, 6 और 10 ने उसे बताया था कि विभिन्न हथियारों से लैस चालीस अन्य लोग हमले में शामिल थे। यह विरोधाभास उसकी विश्वसनीयता पर प्रहार करता है। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-3 ने यह भी कहा कि उसने कभी भी अभियोजन साक्षी-20 को चालीस हमलावरों के नाम नहीं बताए, जिससे गवाह की विश्वसनीयता और कमजोर हो गई।

68. घायल प्रत्यक्षदर्शी गवाह अभियोजन साक्षी-3 ने अपने मौखिक साक्ष्य में क्रमशः आरोपी सं. 12 और 10 पर प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया है। उसने बताया कि आरोपी सं. 10 ने उसके पैर पर गंडासे से हमला किया। हालाँकि, अभिलेख में उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य न केवल यह दर्शाते हैं कि गवाह के पैर पर कोई चोट नहीं थी, बल्कि यह भी कि गंडासे से लगी चोट आमतौर पर एक चीरा हुआ घाव बन जाती है। उसके बयान से यह भी पता चलता है कि वह दो गोलियों की आवाज़ सुनकर घटनास्थल पर बाद में पहुँचा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियोजन साक्षी-20 को चालीस आरोपियों के नाम नहीं बताए थे।

i. **नेत्रसाक्ष्य (प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य) और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास**

69. चिकित्सीय साक्ष्य और नेत्रसाक्ष्य के बीच विरोधाभास संबंधी विधि का संक्षिप्त प्रतिपादन, अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2010) 10 एस.सी.सी. 259 में किया गया है, जिसमें इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है :—

“चिकित्सीय साक्ष्य बनाम नेत्रसाक्ष्य

32. राम नारायण सिंह बनाम पंजाब राज्य, [(1975) 4 एस.सी.सी. 497 : 1975 एस.सी.सी. (क्रि.) 571 : ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1727] में यह प्रतिपादित किया गया कि जहाँ अभियोजन के साक्षियों का साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य या बैलिस्टिक विशेषज्ञ के साक्ष्य से पूर्णतः असंगत हो, वहाँ यह अभियोजन के मामले में एक मूलभूत दोष उत्पन्न करता है और यदि उसका समुचित स्पष्टीकरण न दिया जाए, तो यह संपूर्ण अभियोजन प्रकरण को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त है।”

XXX

38. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि चंद [(2009) 13 एससीसी 542: (2010) 1 एससीसी (क्रि) 1112] में इस न्यायालय ने कानून की उपरोक्त स्थिति को दोहराया और कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 545, कंडिका 13)

“13. ... किसी भी स्थिति में, जब तक मौखिक साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य से पूरी तरह मेल न खाए, उसे प्राथमिकता दी जाती है।”

39. इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य और प्रत्यक्ष साक्ष्य के बीच विरोधाभास है, कानून की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है कि यद्यपि किसी गवाह की प्रत्यक्ष गवाही का चिकित्सीय साक्ष्य की तुलना में अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, लेकिन जब चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्ष गवाही को असंभाव्य बना देता है, तो साक्ष्य के मूल्यांकन की प्रक्रिया में यह एक प्रासंगिक कारक बन जाता है। हालाँकि, जहाँ चिकित्सीय साक्ष्य इतना आगे बढ़ जाता है कि वह प्रत्यक्ष साक्ष्य के सत्य होने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर देता है, वहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।”

(जोर दिया गया)

70. घायल चश्मदीद गवाह, अभियोजन साक्षी-5 ने अपने मौखिक साक्ष्य में क्रमशः आरोपी सं. 8 और 6 पर प्रत्यक्ष रूप से किए गए कृत्यों का आरोप लगाया है। हालाँकि, चिकित्सा साक्ष्य गवाह द्वारा बताए गए हमले के बयान का समर्थन नहीं करता है। हालाँकि दोनों, अर्थात् क्रमशः आरोपी सं. 8 और 6 पर, गवाह पर लाठियों से हमला करने का आरोप है, चिकित्सा साक्ष्य उसके शरीर पर केवल कटे हुए घावों का ही खुलासा करते हैं। उसकी मौखिक गवाही से यह भी संकेत मिलता है कि वह मृतक को गोली लगने के काफी समय बाद घटनास्थल पर पहुँचा था।
71. एक अन्य घायल प्रत्यक्षदर्शी, अभियोजन साक्षी-6 की मौखिक गवाही से पता चलता है कि घटनास्थल पर पहुँचने से पहले ही उस पर हमला किया गया था। अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बयान 30.11.1988 को, यानी घटना के 10 दिन बाद दर्ज किया गया था। जबकि, जाँच अधिकारी के अनुसार, उसने उक्त गवाह का बयान 21.11.1988 को दर्ज किया था। अभियोजन साक्षी-6 ने क्रमशः आरोपी सं. 14, 7 और 13 पर प्रत्यक्ष कृत्यों का आरोप लगाया है; हालाँकि, किसी अन्य गवाह ने क्रमशः आरोपी सं. 14, 7 और 13 की मिलीभगत के बारे में कुछ नहीं कहा है। अभियोजन साक्षी-10 की मौखिक गवाही से यह पता चलता है कि उस पर जल्ला और मसियान नामक व्यक्तियों ने हमला किया था, जिनका न तो प्राथमिकी में नाम था और न ही आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। उसने पुलिस के सामने यह कहने से भी इनकार किया कि आरोपी सं. 10 ने उस पर हमला किया था।
72. इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-4 की मौखिक गवाही से महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने किसी भी अपीलकर्ता की उपस्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत, उसने कहा कि घटनास्थल पर बड़ी सं. में लोग मौजूद थे, और वह हमलावरों और दर्शकों के बीच अंतर नहीं कर पाया। हालाँकि, अभियोजन साक्षी-23, यानी जाँच अधिकारी, ने गवाही दी है कि अभियोजन साक्षी-4 ने उसके सामने कई नामों का खुलासा किया था। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी-8 ने यह नहीं बताया कि आरोपी सं. 14, 11 और 17 ने क्रमशः उसके पति पर हमला किया था। वास्तव में, उसने अलग-अलग नामों का भी खुलासा किया था।
73. वर्तमान मामले में, विवेक की माँग है कि हमें केवल उन आरोपियों की उपस्थिति या भागीदारी पर विश्वास करना चाहिए जो कम से कम दो विश्वसनीय गवाहों की सहायता

से संतोषजनक रूप से स्थापित हो चुके हों। क्रमशः आरोपी 3 और 5 की मौखिक गवाही में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं।

74. इसी प्रकार, आरोपी सं. 7, 13 और 14 को क्रमशः केवल आरोपी-6 द्वारा ही आरोपित किया गया है। उनकी उपस्थिति या भागीदारी किसी अन्य गवाह की गवाही से समर्थित नहीं है, न ही अभिलेखों में मौजूद किसी भी अंतर्निहित साक्ष्य से। जहाँ तक आरोपी सं. 9 का संबंध है, उसके विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य आरोपी-20 द्वारा की गई पहचान है, जो किसी भी सहायक साक्ष्य के अभाव में, उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। आरोपी सं. 10 की उपस्थिति भी संदिग्ध है।
75. अभियोजन साक्षी-3 के अनुसार, आरोपी सं. 10 ने उस पर गंडासे से हमला किया था। हालाँकि, साक्ष्य कुछ और ही बताते हैं। अभियोजन साक्षी-20 के कहने पर दर्ज किए गए फर्दबयान में आरोपी सं. 10 का नाम हमलावरों में नहीं है। इसके अलावा, आरोपी सं. 11 और 12 की उपस्थिति या भागीदारी को दर्शाने वाला कोई भी ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है। अंत में, अभियोजन साक्षी-20 द्वारा की गई एक विस्तृत पहचान के अलावा, आरोपी सं. 17 के खिलाफ भी कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।
76. इस मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण से, हमारा मानना है कि आरोपी सं. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 क्रमशः संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। कानून की नज़र में उनकी दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती।
77. एक आम आदमी यह तर्क दे सकता है कि अगर सभी चश्मदीद गवाहों पर विश्वास नहीं किया जाना है, तो उन्हें लगी विभिन्न चोटों की व्याख्या कौन करेगा। दूसरे शब्दों में, एक आम आदमी यह कह सकता है कि आरोपियों का मामला तो यह भी नहीं है कि चश्मदीद गवाहों को कोई चोट नहीं लगी या उन्होंने खुद ही चोटें पहुँचाईं। ऐसी स्थिति में, चश्मदीद गवाहों पर पूरी तरह से विश्वास क्यों नहीं किया जाना चाहिए?
78. इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि चश्मदीद गवाहों को लगी चोटें, ज़्यादा से ज़्यादा, घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी सुनिश्चित कर सकती हैं, लेकिन यह काफ़ी नहीं है। किसी भी आपराधिक न्यायालय को किसी घायल चश्मदीद गवाह की गवाही स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वह एक सच्चा गवाह है और उसके पास आरोपियों को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था। हमने सभी चश्मदीद गवाहों के मौखिक साक्ष्य में विभिन्न कमियों की विस्तार से व्याख्या की है, या यूँ कहें कि चर्चा

की है। इन चश्मदीद गवाहों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज अपने पुलिस बयानों में उन लोगों को भी फंसाने की हद तक कोशिश की है, जिन्हें अंततः आरोपपत्र में आरोपी नहीं बनाया गया था, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अंततः विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था।

79. वर्तमान जैसे मामलों में न्यायालयों को सत्य को असत्य से, तथा सार को निरर्थक से पृथक करने का प्रयास करना चाहिए, किन्तु यह तभी संभव है जब सत्य, असत्य से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके।
80. उपर्युक्त संदर्भ में, हम **बालाका सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य** में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जो (1975) 4 एससीसी 511 में दर्ज है। कंडिका 8 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:-

“8. अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष पिछले हत्याकांड में गुरनाम सिंह की हत्या के लिए बालाका सिंह को दोषी ठहराने में सफल नहीं हो सका। आरोपियों से नया बदला लेने के लिए ही उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह सच है कि आठ गवाह ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने घटना देखी थी और उन्होंने विभिन्न आरोपियों द्वारा मृतक पर हमले के बारे में पूरे मामले का एक रटा-रटाया विवरण दिया है। इन सभी गवाहों ने एक स्वर और पूरी एकमतता से उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए चार आरोपियों को भी दोषी ठहराया है, जबकि अपीलकर्ताओं ने भी एक-दूसरे में कोई भेद नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं और चारों आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष का मामला इतना उलझा हुआ है कि एक को दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। यह सत्य है कि, जैसा कि इस न्यायालय ने ज्विंगली एरियल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1952) 2 एससीसी 560 : एआईआर 1954 एससी 15 : 1954 क्रि एलजे 230] और उस मामले के बाद आए अन्य मामलों में निर्धारित किया है, न्यायालय को अनाज को भूसे से, सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास करना चाहिए, फिर भी यह तभी संभव हो सकता है जब सत्य को असत्य से अलग किया जा सके। जहां अनाज को भूसे से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनाज और भूसा इतने अभिन्न रूप से मिश्रित हैं

कि अलग करने की प्रक्रिया में न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को उस संदर्भ और पृष्ठभूमि से पूरी तरह अलग करके अभियोजन पक्ष के लिए एक बिल्कुल नया मामला फिर से बनाना होगा, जिसके खिलाफ उन्हें बनाया गया था, तब यह सिद्धांत लागू नहीं होगा।[...]”

(जोर दिया गया)

ग. क्या यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है?

81. **रमाकांत राय बनाम मदन राय**, (2003) 12 एससीसी 395 में, इस न्यायालय ने "उचित संदेह" का अर्थ स्पष्ट किया था। इसका अर्थ है ऐसे संदेह जो अमूर्त अटकलों से मुक्त हों, किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम न हों, जो आरोपी के अपराध पर वास्तविक और ठोस संदेह हों, न कि अस्पष्ट आशंकाएँ। यह कोई काल्पनिक, तुच्छ या संभावित संदेह नहीं हो सकता, बल्कि तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित संदेह हो सकता है। प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:-

“23. किसी व्यक्ति को निस्संदेह, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी न ठहराए जाने का गहरा अधिकार है जो उचित संदेह से परे सबूत के साक्ष्य मानक द्वारा स्थापित नहीं होता है। हालांकि यह मानक एक उच्चतर मानक है, फिर भी, कोई पूर्ण मानक नहीं है। किस हद तक संभाव्यता “प्रमाण” के बराबर है, यह प्रत्येक मामले के लिए एक विशेष अभ्यास है। संभाव्यता के “प्रमाण” के बराबर होने का उल्लेख करना एक अभ्यास है, साक्ष्य की अन्योन्याश्रयता और एक साक्ष्य द्वारा दूसरे साक्ष्य की पुष्टि, जैसा कि विद्वान लेखक कहते हैं: [देखें सबूत का गणित II: ग्लेनविले विलियम्स, आपराधिक कानून समीक्षा, 1979, स्वीट और मैक्सवेल द्वारा, पृष्ठ 340 (342)]

“यदि साक्ष्य के पृथक-पृथक अंश एक-दूसरे पर निर्भर हों तो साधारण गुणन का नियम लागू नहीं होता। दो घटनाएँ तब परस्पर निर्भर होती हैं जब वे साथ-साथ घटित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, और ऐसी घटनाओं से संबंधित साक्ष्य भी निर्भर माने जा सकते हैं। एक आपराधिक मामले में, अभियुक्त द्वारा निषिद्ध कृत्य को निर्दिष्ट मानसिक अवस्था के साथ किए जाने को स्थापित करने हेतु प्रस्तुत विभिन्न साक्ष्य सामान्यतः परस्पर निर्भर होते हैं। कोई

निर्णायक इस बात पर संदेह कर सकता है कि कथित स्वीकारोक्ति पर विश्वास किया जाए या नहीं, और इस बात पर भी संदेह कर सकता है कि अभियुक्त के न्याय से भागने के तथ्य से दोषिता का अनुमान लगाया जाए या नहीं। किन्तु चूँकि सामान्यतः निर्दोष व्यक्तियों की अपेक्षा दोषी व्यक्ति ही स्वीकारोक्ति करते हैं और निर्दोष व्यक्तियों की अपेक्षा दोषी व्यक्ति ही भागते हैं, इसलिए इन दोनों संदेहों को परस्पर गुणा नहीं किया जाना चाहिए। एक साक्ष्य दूसरे साक्ष्य की पुष्टि कर सकता है।”

24. संदेहों को युक्तिसंगत तब कहा जाएगा जब वे अमूर्त कल्पनाओं की प्रवृत्ति से मुक्त हों। विधि सत्य के अतिरिक्त किसी अन्य को कोई वरीयता प्रदान नहीं कर सकती। किसी संदेह को युक्तिसंगत होने के लिए आवश्यक है कि वह अतिशय भावनात्मक प्रतिक्रिया से मुक्त हो। संदेह वास्तविक और ठोस होने चाहिए, जो अभियुक्त व्यक्तियों की दोषिता के संबंध में साक्ष्य से उत्पन्न हों या उसके अभाव से उत्पन्न हों, न कि केवल अस्पष्ट आशंकाएँ हों। युक्तिसंगत संदेह न तो काल्पनिक होता है, न तुच्छ और न ही मात्र संभावित संदेह; यह ऐसा निष्पक्ष संदेह है जो तर्क और सामान्य बुद्धि पर आधारित होता है। यह वाद में उपलब्ध साक्ष्य से उत्पन्न होना चाहिए।

25. प्रायिकता की संकल्पनाएँ और उसकी मात्राएँ, स्पष्टतः इस प्रकार गणितीय इकाइयों में व्यक्त नहीं की जा सकती कि यह निर्धारित किया जा सके कि कितनी ऐसी इकाइयाँ ‘युक्तिसंगत संदेह से परे प्रमाण’ का निर्माण करती हैं। प्रायिकता की मात्राओं तथा प्रमाण की परिमाण के मूल्यांकन में एक स्पष्ट व्यक्तिपरक तत्व निहित होता है। विधिविज्ञान प्रायिकता को अंततः सुदृढ सामान्य बुद्धि पर तथा अंतिम विश्लेषण में न्यायाधीश की प्रशिक्षित अंतर्दृष्टि पर आधारित होना चाहिए। यद्यपि आपराधिक प्रक्रिया द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों को प्रदान की गई सुरक्षा को क्षीण नहीं किया जाना चाहिए, तथापि तुच्छताओं को अज्ञानतावश वैधता प्रदान करना आपराधिक न्याय के प्रशासन का उपहास होगा। इस स्थिति को माननीय न्यायमूर्ति वेंकटचलैया (तत्कालीन) द्वारा ‘उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण गोपाल’ [(1988) 4 एस.सी.सी. 302 : 1988 एस.सी.सी. (क्रि.) 928 : ए.आई.आर. 1988 एस.सी. 2154] में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया था।”

(जोर दिया गया)

82. यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है। एक मामला उस मानक तक पहुँचता है जब उसके सभी संबंध दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं और एक विवेकशील व्यक्ति की नज़र में पहचाने जा सकते हैं। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का कथन तथ्यों के सत्य वर्णन से उत्पन्न नहीं प्रतीत होता है।
83. गवाहों की मौखिक गवाही न तो एक-दूसरे की पुष्टि करती है और न ही मेडिकल अभिलेख से मेल खाती है। महत्वपूर्ण चूकों के रूप में विभिन्न विरोधाभास मामले की जड़ तक पहुँचते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में, यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपना साक्ष्य भार पूरा कर लिया है।

ख. क्या अभियोजन साक्षी-20 के बयान को प्राथमिकी माना जा सकता था?

84. जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अभियोजन साक्षी-20 के बयान के आधार पर दर्ज प्राथमिकी में 72 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से कई का अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कोई ज़िक्र नहीं है। इन 72 आरोपियों में से केवल 24 के खिलाफ ही आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिन पर अंततः मुकदमा चलाया गया। वास्तव में चिंताजनक बात यह है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ प्रत्यक्ष और विशिष्ट आरोप लगाए गए थे, उनका नाम या तो प्राथमिकी में नहीं है या फिर उन्हें आरोपपत्र से बेवजह हटा दिया गया है। अभिलेख में मौजूद सामग्री से यह पता नहीं चलता कि पुलिस ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, अगर कोई की भी गई।
85. हम एक और प्रासंगिक मुद्दे पर विचार करना आवश्यक समझते हैं। घायल प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के मौखिक साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी-20 के फर्दबयान को प्राथमिकी नहीं माना जा सकता था। अभियोजन साक्षी 3, 4, 5, 8 और 22 के मौखिक साक्ष्यों के मात्र अवलोकन से ही पता चलता है कि अपराध के घटित होने की सूचना अभियोजन साक्षी-20 के बयान दर्ज होने और प्राथमिकी दर्ज होने से बहुत पहले ही पुलिस तक पहुँच गई थी। हम निम्नलिखित साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं:

क. सबसे पहले, जाँच अधिकारी (अभियोजन साक्षी-23) के मौखिक साक्ष्य से पता

चलता है कि उन्हें सरकारी अस्पताल, आजम नगर से एक ओ.डी. पर्ची प्राप्त हुई थी, और उसके बाद, वे अभियोजन साक्षी-20 का फर्दबयान दर्ज करने के लिए अस्पताल गए। जबकि अभियोजन साक्षी-22 (सरकारी अस्पताल, आजम नगर के चिकित्सा अधिकारी) ने बताया कि उन्होंने पुलिस के अनुरोध पर घायलों की जाँच की थी।

ख. दूसरे, अभियोजन साक्षी-23 अर्थात जाँच अधिकारी के मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने अभियोजन साक्षी-20 का बयान लगभग 1:25 अपराह्न पर दर्ज किया था।

i. हालाँकि, अभियोजन साक्षी-3 ने गवाही दी कि जब उसे घटनास्थल पर होश आया, तो उसने देखा कि पुलिस आ गई है। यह लगभग सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे का समय था, और उसका बयान दर्ज किया गया।

ii. दूसरी ओर, अभियोजन साक्षी-5 ने कहा कि उसे अस्पताल ले जाते समय नाव में होश आया, और सभी घायल व्यक्ति लगभग सुबह 9 बजे थाना गए, जहाँ उनके बयान दर्ज किए गए, और उसके बाद अस्पताल गए।

iii. घटना के एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी अभियोजन साक्षी-4 ने बताया कि घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के बाद, पुलिस लगभग दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच घटनास्थल पर पहुँची और उसका बयान दर्ज किया। इस संबंध में अभियोजन साक्षी-4 की गवाही अभियोजन साक्षी-8 की गवाही से पुष्ट होती है। उसने कहा कि पुलिस घटना के लगभग दो घंटे बाद पहुँची और उससे पूछताछ की।

ग. तीसरा, अभियोजन साक्षी-20 ने अपने मौखिक साक्ष्य में स्वीकार किया कि हमले के बाद वह बेहोश हो गया था, और इसलिए वह मृतक के हमलावरों और अभियोजन साक्षी 3, 6 और 10 को पहचानने में असमर्थ था। जबकि, पुलिस को दिए गए उसके फर्दबयान/बयान में यह दर्ज है कि अभियोजन साक्षी 3, 5, 6 और 10 ने उसे बताया था कि विभिन्न हथियारों से लैस चालीस अन्य व्यक्तियों ने उन पर हमला किया था।

86. उपरोक्त से, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी-20 के बयान को प्राथमिकी नहीं

माना जा सकता था, क्योंकि घटना की पहली सूचना अस्पताल में बयान दर्ज होने से पहले ही पुलिस तक पहुँच चुकी थी। परिणामस्वरूप, अभियोजन साक्षी-20 का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज पुलिस बयान बन जाता है।

87. **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनाती रामुलु एवं अन्य, 1994 के अनुपूरक (1) एससीसी 590** में दर्ज मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि यदि यह पाया जाता है कि जाँच अधिकारी ने संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जानबूझकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की, और विचार-विमर्श, परामर्श और चर्चा के बाद प्राथमिकी तैयार की, तो प्राथमिकी विश्वास पैदा करने में विफल रहेगी। प्रासंगिक टिप्पणियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:-

“5.[...] जब हम यह पाते हैं कि अन्वेषण पदाधिकारी ने इस प्रकार के संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर जानबूझकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन अभिलिखित नहीं किया और पर्याप्त विचार-विमर्श, परामर्श तथा चर्चा के पश्चात घटनास्थल पर पहुँचकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन तैयार किया, तब यह निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है कि अन्वेषण दूषित है और इसलिए ऐसे दूषित अन्वेषण पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पुलिस पदाधिकारी मिथ्या साक्ष्य गढ़ने तथा झूठे सूत्र उत्पन्न करने के लिए कहाँ तक गया होगा। यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि अभियोजन साक्षी 3 तथा अभियोजन साक्षी 4, जो मृतक की संतानें हैं, अथवा अभियोजन साक्षी 1 और अभियोजन साक्षी 2, जो भी मृतक से संबंधित हैं, का मात्र संबंधी होना अपने-आप में उनकी साक्ष्य को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा यह कि संबंध या साक्ष्य का पक्षपातपूर्ण स्वरूप न्यायालय पर केवल यह दायित्व डालता है कि वह साक्ष्य की अधिक सावधानीपूर्वक जाँच-परख करे, तथापि हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में जब अन्वेषण की सद्भावना पर सफलतापूर्वक प्रहार किया जा चुका है, तब इन साक्षियों की साक्ष्य पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसे अत्यंत प्रभावशाली प्रकृति के सुदृढ़ पुष्टिकारक साक्ष्य का समर्थन प्राप्त न हो; और ऐसे साक्ष्य का इस मामले में अभाव है।”

(जोर दिया गया)

88. **रणबीर यादव बनाम बिहार राज्य, (1995) 4 एससीसी 392** में दर्ज मामले में, पुलिस अधिकारी ने रात में हुए दंगे की जाँच शुरू कर दी थी, लेकिन उसने जिन लोगों से

बात की, उनमें से किसी का भी बयान दर्ज नहीं किया। घटना की प्राथमिकी अगली सुबह एक गवाह द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही दर्ज की गई। इस न्यायालय ने माना कि विचारण न्यायालयों ने बयान को प्राथमिकी मानकर गलती की, क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत एक बयान था। प्रासंगिक अंश निम्नलिखित हैं:-

“38. अभियोजन साक्षी 96 के साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद, हम यह कहने के लिए विवश हैं कि विचारण न्यायालयों द्वारा प्रविष्ट 10/1 को प्राथमिकी मानना न्यायोचित नहीं था। निस्संदेह, अभियोजन साक्षी 96, सुबह हुई घटना के संबंध में दर्ज दो मुकदमों की जाँच करने के लिए 11-11-1985 की रात को लक्ष्मीपुर बिंद टोली गाँव पहुँचा था। उसने गवाही दी कि रात 10.30 बजे गाँव पहुँचने पर उसे दूसरी घटना की भी जानकारी मिली और इस संबंध में उसने कई लोगों से बात की। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने उन लोगों के बयान दर्ज नहीं किए जिनसे उन्होंने बात की थी। प्रतिपरीक्षण में उनसे यह पता चला कि जिस रात उन्हें पता चला कि कुछ लोगों के घरों को लूट लिया गया और आग लगा दी गई, कुछ लोगों की हत्या कर दी गई और कुछ ग्रामीणों का पता नहीं चल पाया। आगे प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वेच्छा से बताया कि उन्होंने उसी रात दूसरी घटना पर दर्ज मामले की जाँच शुरू कर दी थी। अभियोजन साक्षी 96 के ऐसे स्वीकारोक्ति और दूसरी घटना के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न जाँच चरणों को देखते हुए, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि अगली सुबह अभियोजन साक्षी 1 द्वारा दर्ज की गई प्रतिवेदन को केवल संहिता की धारा 161(3) के अनुसार दर्ज एक बयान के रूप में माना जा सकता है, न कि एक प्राथमिकी के रूप में। इसलिए, अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन साक्षी 1 का साक्ष्य अग्राह्य है जैसा कि श्री जेठमलानी ने तर्क दिया है।

(जोर दिया गया)

89. इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राथमिकी में सूचना देने वाले द्वारा दी गई जानकारी उसी समय पूरी तरह से दर्शाई जानी चाहिए जब वह दर्ज की गई हो। किसी सूचना को प्राथमिकी मानने की असली कसौटी यह है कि क्या वह पुलिस अधिकारी को किसी

संज्ञेय अपराध के होने का संदेह करने का आधार प्रदान कर सकती है। एक बार यह आवश्यकता पूरी हो जाने पर, अधिकारी उसे लिखित रूप में दर्ज करने के लिए बाध्य है।

90. वर्तमान मामले में, स्वाभाविक घटनाक्रम में, आरोपी सं. 3, 4, 5 और 8 ने पुलिस को कथित अपराध के घटित होने का खुलासा कर दिया होता। दोनों हत्याओं से संबंधित पहले बयान को ही प्राथमिकी माना जाना चाहिए था। हालाँकि, गवाहों के थाने आने, जाँच अधिकारी के घटनास्थल पर जाने, या यहाँ तक कि जाँच अधिकारी के अस्पताल जाने के बारे में पुलिस थाने की दैनिक डायरी या रोज़नामचा प्रविष्टि को अभिलेख में नहीं लाया गया, जिससे प्राथमिकी की प्रामाणिकता पर और संदेह पैदा होता है। ऐसी परिस्थितियों में, आरोपी सं. 20 का बयान, जिसे प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया है, विश्वास पैदा करने में विफल रहता है।

VI निष्कर्ष

91. परिणामस्वरूप, अपीलें सफल होती हैं और एतद्वारा स्वीकार की जाती हैं। अपीलकर्ताओं को उन अपराधों के लिए दोषी ठहराने के लिए पारित किया गया आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिनका उन पर आरोप लगाया गया था, अपास्त किया जाता है। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को बरी किया जाता है। उनके जमानत बांड निरस्त माने जाते हैं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

† जिनके द्वारा हेडनोट तैयार किया गया : अंकित ज्ञान

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।